FREE DEMO SAMPLE

Guessing Paper 2026-27 Demo Set

B.A. · Semester 5 · International Politics: Theory and Practice

ABVV Bilaspur — अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर

यह सिर्फ़ एक डेमो सेट है 📘

इस डेमो से आप हमारे उत्तरों की क्वालिटी और पेपर का फ़ॉर्मेट देख सकते हैं। **असली 3 पूरे Guessing Paper सेट** (Set A, B, C) सिर्फ़ **Pariksha Pass App** में मिलते हैं:

- हर विषय के **3 पूरे सेट** — Most Probable, Highly Likely और Alternate
- हर प्रश्न का **सटीक मॉडल उत्तर** — हिंदी और English दोनों में
- **Year Tag** — जो प्रश्न पहले यूनिवर्सिटी परीक्षा में आ चुके हैं
- आपकी **यूनिवर्सिटी के पैटर्न** पर — पूरा सिलेबस कवर

▶ Pariksha Pass App डाउनलोड करें
यहाँ टैप करें — Google Play पर उपलब्ध

QR स्कैन करें

इस डेमो के प्रश्न असली Set A/B/C से नहीं लिए गए हैं। कोई भी पेपर परीक्षा में प्रश्न आने की गारंटी नहीं देता — इसे पाठ्यपुस्तक के साथ अभ्यास के लिए उपयोग करें। · Free sample shared on cguniversities.com

Paper Code: **PSSC-05**
Demo Set

Roll No. | | | | | | | | | | |

BILASPUR UNIVERSITY, BILASPUR (C.G.)
बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

B.A. (Fifth Semester) Examination, Nov.–Dec. 2026
बी.ए. (पंचम सेमेस्टर) परीक्षा, नवम्बर–दिसम्बर 2026

POLITICAL SCIENCE - INTERNATIONAL POLITICS: THEORY AND PRACTICE
राजनीति विज्ञान - अंतर्राष्ट्रीय राजनीति: सिद्धांत और व्यवहार

Time / **समय** : 3 Hours	Maximum Marks / **पूर्णांक** : 70

DEMO SAMPLE – not from the actual sets · prepared by Online Student Seva for the Pariksha Pass App · not an official University question paper

Instructions:

1. Section A: Q.1 (objective) is compulsory. Attempt any 4 of the 5 short-answer questions in Q.2.
2. Section B: attempt **one** question from each unit (Q.3 to Q.6); each has an internal choice.
3. Figures in the right margin show full marks. Draw neat, labelled diagrams wherever necessary.

निर्देश : खण्ड-अ में प्रश्न 1 अनिवार्य है; प्रश्न 2 के 5 में से 4 प्रश्न हल करें। खण्ड-ब में प्रत्येक इकाई से **एक** प्रश्न हल करें (प्रश्न 3 से 6), सभी में आंतरिक विकल्प है। दाईं ओर के अंक पूर्णांक दर्शाते हैं। आवश्यकतानुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाएँ।

SECTION – A / खण्ड – अ

Q.1 **Choose the correct answer.** सही उत्तर चुनिए। 10 × 1 = 10

(1) The term 'soft power' in international politics was coined by:
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 'सॉफ्ट पावर' शब्द किसने गढ़ा?

(a) Hans Morgenthau / हंस मॉर्गेंथाउ
(b) Joseph Nye / जोसेफ नाय
(c) Kenneth Waltz / केनेथ वाल्ट्ज़
(d) Henry Kissinger / हेनरी किसिंजर

(2) The Peace of Westphalia (1648) is regarded as the beginning of the modern:
वेस्टफेलिया की संधि (1648) को आधुनिक किसकी शुरुआत माना जाता है?

(a) League of Nations system / राष्ट्र संघ व्यवस्था
(b) Cold War order / शीत युद्ध व्यवस्था
(c) nation-state system / राष्ट्र-राज्य व्यवस्था
(d) colonial system / उपनिवेशवादी व्यवस्था

(3) Amnesty International is an example of a:
एमनेस्टी इंटरनेशनल किसका उदाहरण है?

(a) military alliance / सैनिक गठबंधन
(b) regional government / क्षेत्रीय सरकार
(c) foreign ministry / विदेश मंत्रालय
(d) international non-governmental organisation (a non-state actor) / अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (एक गैर-राज्य कर्ता)

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

(4) The Anti-Ballistic Missile (ABM) Treaty of 1972 between the USA and the USSR limited:
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1972 की ए.बी.एम. संधि ने किसे सीमित किया?

(a) anti-ballistic missile defence systems / प्रक्षेपास्त्र-रोधी (एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल) रक्षा प्रणालियाँ
(b) underground nuclear tests / भूमिगत परमाणु परीक्षण
(c) chemical weapons / रासायनिक हथियार
(d) conventional forces in Europe / यूरोप में परंपरागत सेनाएँ

(5) The ability of a state to retaliate even after absorbing a nuclear first strike is called:
परमाणु पहले हमले को सहने के बाद भी जवाबी हमला करने की राज्य की क्षमता क्या कहलाती है?

(a) Detente / तनाव-शैथिल्य (दितांत)
(b) Second-strike capability / द्वितीय-प्रहार क्षमता
(c) Containment / containment (अवरोध)
(d) Brinkmanship / कगार की नीति (ब्रिंकमैनशिप)

(6) The Non-Proliferation Treaty (NPT) defines a 'nuclear-weapon state' as one that had made and exploded a nuclear device before:
परमाणु अप्रसार संधि (NPT) 'परमाणु-शस्त्र संपन्न राज्य' उसे मानती है जिसने किस तिथि से पहले परमाणु उपकरण बनाकर विस्फोट किया हो:

(a) 1 January 1945 / 1 जनवरी 1945
(b) 1 January 1967 / 1 जनवरी 1967
(c) 1 July 1968 / 1 जुलाई 1968
(d) 1 January 1996 / 1 जनवरी 1996

(7) Winston Churchill delivered his 'Iron Curtain' speech in 1946 at:
विंस्टन चर्चिल ने 1946 में अपना 'आयरन कर्टेन' भाषण कहाँ दिया?

(a) London / लंदन
(b) Yalta / याल्टा
(c) Potsdam / पॉट्सडैम
(d) Fulton, Missouri (USA) / फुल्टन, मिसौरी (अमेरिका)

(8) COMECON (1949) was an economic organisation of the:
कॉमेकॉन (1949) किसका आर्थिक संगठन था?

(a) Soviet bloc (the USSR and its allies) / सोवियत गुट (सोवियत संघ और उसके सहयोगी)
(b) NATO countries / नाटो देश
(c) non-aligned countries / गुटनिरपेक्ष देश
(d) European Union / यूरोपीय संघ

(9) The International Criminal Court (ICC) was established by the:
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आई.सी.सी.) की स्थापना किसके द्वारा हुई?

(a) Geneva Conventions / जेनेवा अभिसमय
(b) Rome Statute (1998) / रोम संविधि (1998)
(c) Treaty of Versailles / वर्साय की संधि
(d) UN Charter / संयुक्त राष्ट्र चार्टर

(10) The principle of 'Responsibility to Protect' (R2P) was endorsed by UN member states at the:
'संरक्षण का दायित्व' (आर2पी) सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने कहाँ अपनाया?

(a) 1945 San Francisco Conference / 1945 का सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन
(b) 1992 Earth Summit / 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन
(c) 2005 World Summit / 2005 का विश्व शिखर सम्मेलन
(d) 2015 Paris Conference / 2015 का पेरिस सम्मेलन

Q.2 **Attempt any 4 of the following 5 questions.** निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। **4 × 5 = 20**

(a) Write a short note on the Peace of Westphalia (1648). **5**
वेस्टफेलिया की संधि (1648) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

(b) What is the 'security dilemma'? Explain with an example. **5**
'सुरक्षा दुविधा' (सिक्योरिटी डिलेमा) क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।

(c) Write a short note on Churchill's 'Iron Curtain' speech (1946). **5**
चर्चिल के 'आयरन कर्टेन' भाषण (1946) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(d) Distinguish between peacekeeping and peace enforcement in the work of the United Nations. **5**
संयुक्त राष्ट्र के कार्य में शांति-स्थापना (पीसकीपिंग) और शांति-प्रवर्तन (पीस एनफ़ोर्समेंट) में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(e) What is the 'two-state solution' in the Palestine-Israel conflict? State the main issues on which it is stuck. **5**
फ़लस्तीन-इज़राइल संघर्ष में 'द्वि-राष्ट्र समाधान' क्या है? उन मुख्य मुद्दों को बताइए जिन पर यह अटका है।

SECTION – B / खण्ड – ब

Long answer questions · one question from each unit with internal choice / **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

Q.3 Explain the concepts of hard power, soft power and smart power. How do they influence a state's position in international politics? **10**
कठोर शक्ति (हार्ड पावर), मृदु शक्ति (सॉफ्ट पावर) और स्मार्ट शक्ति की अवधारणाओं को समझाइए। ये किसी राज्य की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं?

OR / अथवा

Explain Neo-realism (Structural Realism) of Kenneth Waltz. How does it differ from classical Realism, and what are its limitations?
केनेथ वॉल्ट्ज़ के नव-यथार्थवाद (संरचनात्मक यथार्थवाद) को समझाइए। यह परंपरागत यथार्थवाद से कैसे भिन्न है और इसकी सीमाएँ क्या हैं?

Q.4 Explain the theory of nuclear deterrence and Mutually Assured Destruction (MAD). What are its conditions and criticisms? **10**
परमाणु निवारण (डेटरेंस) के सिद्धांत और परस्पर सुनिश्चित विनाश (MAD) को समझाइए। इसकी शर्तें और आलोचनाएँ क्या हैं?

OR / अथवा

Discuss the major US-Soviet (US-Russian) arms control agreements: SALT, the INF Treaty and START. How far did they succeed?
अमेरिका-सोवियत (अमेरिका-रूस) के प्रमुख शस्त्र-नियंत्रण समझौतों, यानी साल्ट, आई.एन.एफ. संधि और स्टार्ट की चर्चा कीजिए। वे कहाँ तक सफल रहे?

Q.5 Describe the Cuban Missile Crisis of 1962: its background, main events, resolution and importance in the Cold War. **10**
1962 के क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन कीजिए: उसकी पृष्ठभूमि, प्रमुख घटनाएँ, समाधान और शीत युद्ध में उसका महत्व।

OR / अथवा

Explain the origin, principles and role of the Non-Aligned Movement (NAM). Is it still relevant after the end of the Cold War?
गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की उत्पत्ति, सिद्धांतों और भूमिका को समझाइए। क्या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह प्रासंगिक है?

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Q.6 Discuss the basic principles of India's foreign policy with special reference to Panchsheel, the Gujral Doctrine and the 'Neighbourhood First' policy. 10
पंचशील, गुजराल सिद्धांत और 'पड़ोसी पहले' नीति के विशेष संदर्भ में भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।

OR / अथवा

Explain the UN's peacekeeping operations and the doctrine of the 'Responsibility to Protect' (R2P). Assess their successes and failures.
संयुक्त राष्ट्र के शांति-स्थापना अभियानों और 'संरक्षण की ज़िम्मेदारी' (R2P) के सिद्धांत को समझाइए। उनकी सफलताओं और विफलताओं का मूल्यांकन कीजिए।

— END OF QUESTION PAPER · प्रश्न-पत्र समाप्त —

ONLINE STUDENT SEVA · PARIKSHA PASS

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

How to use this Demo Set इस डेमो सेट का उपयोग कैसे करें

DEMO SAMPLE – not from the actual sets. This Demo Set has the same layout, length and answer standard as the full Guessing Papers: question paper, syllabus coverage page, model answers in English and Hindi, and an exam-strategy page. The questions in it were chosen only to show the quality of the answers. They are **not** the questions of the paid sets.

डेमो नमूना – वास्तविक सेटों के प्रश्न नहीं। इस डेमो सेट का ढाँचा, लंबाई और उत्तरों का स्तर पूरे गेसिंग पेपर जैसा ही है: प्रश्न-पत्र, पाठ्यक्रम-कवरेज पृष्ठ, हिन्दी व अंग्रेज़ी में आदर्श उत्तर और परीक्षा-रणनीति। इसके प्रश्न केवल उत्तरों की गुणवत्ता दिखाने के लिए चुने गए हैं; ये पेड सेटों के प्रश्न **नहीं** हैं।

Five ways to get the most out of it

1. Attempt the question paper first, without looking at the answers, and keep to the time limit.
2. Compare your answers with the model answers. Notice the order: introduction or definition, headed sections, a table or diagram, and a conclusion.
3. Learn the structure, then write in your own words. Copying lines word for word does not earn extra marks.
4. Practise the labelled diagrams by hand. They are part of a good 10-mark answer.
5. Read the syllabus and your prescribed books for the whole subject; use this paper to practise writing and time management.

इसका अधिकतम लाभ लेने के पाँच तरीके

1. पहले उत्तर देखे बिना प्रश्न-पत्र हल करें और समय-सीमा का पालन करें।
2. अपने उत्तरों को आदर्श उत्तरों से मिलाएँ। क्रम देखें: भूमिका या परिभाषा, शीर्षकों वाले भाग, तालिका या चित्र और निष्कर्ष।
3. ढाँचा सीखें, फिर अपने शब्दों में लिखें। शब्द-दर-शब्द नकल से अतिरिक्त अंक नहीं मिलते।
4. नामांकित चित्र हाथ से बनाने का अभ्यास करें। ये 10 अंक के अच्छे उत्तर का हिस्सा हैं।
5. पूरे विषय के लिए पाठ्यक्रम और अनुशंसित पुस्तकें पढ़ें; इस पेपर का उपयोग लेखन-अभ्यास और समय-प्रबंधन के लिए करें।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Syllabus Coverage & Reference Books पाठ्यक्रम कवरेज एवं संदर्भ ग्रंथ

This paper follows the official **Political Science - International Politics: Theory and Practice** syllabus (PSSC-05) of the Chhattisgarh Higher Education Department (NEP-2020). The table shows what each unit contains and where this paper tests it.

Unit	Syllabus content (as prescribed)	Questions in this set
1	**Introduction and Approaches** Meaning, definitions, nature and scope of international politics; approaches: Realism, Idealism, Neo-realism, World System theory and Centre-Periphery theory; national interest and national power (meaning, definition, elements); non-state actors (concept, types, influence). **परिचय और उपागम** — अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, परिभाषाएँ, प्रकृति और क्षेत्र; उपागम: यथार्थवाद, आदर्शवाद, नव-यथार्थवाद, विश्व-व्यवस्था सिद्धांत और केंद्र-परिधि सिद्धांत; राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति (अर्थ, परिभाषा, तत्व); गैर-राज्य अभिकर्ता (अवधारणा, प्रकार, प्रभाव)।	Q.1(1), Q.1(2), Q.1(3), Q.2(a), Q.3
2	**Theories and Concepts** System theory, game theory, decision-making theory, bargaining theory; diplomacy, balance of power, collective security; arms race and disarmament; nuclear disarmament and non-proliferation. **सिद्धांत और अवधारणाएँ** — व्यवस्था सिद्धांत, खेल सिद्धांत, निर्णय-निर्माण सिद्धांत, सौदेबाज़ी सिद्धांत; कूटनीति, शक्ति-संतुलन, सामूहिक सुरक्षा; शस्त्र-होड़ और निःशस्त्रीकरण; परमाणु निःशस्त्रीकरण और अप्रसार।	Q.1(4), Q.1(5), Q.1(6), Q.2(b), Q.4
3	**Cold War and After** Causes of the Second World War and post-war peace agreements; the Cold War: development and major military alliances; end of the Cold War: causes and consequences; detente and new detente; new world order; North-South and South-South cooperation. **शीत युद्ध और उसके बाद** — द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और युद्धोत्तर शांति समझौते; शीत युद्ध: विकास और प्रमुख सैन्य गठबंधन; शीत युद्ध का अंत: कारण और परिणाम; तनाव-शैथिल्य और नया तनाव-शैथिल्य; नई विश्व व्यवस्था; उत्तर-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग।	Q.1(7), Q.1(8), Q.2(c), Q.5
4	**UNO and Major Issues** Foreign policy: concept and determinants; role of the United Nations in world peace and arms control; international terrorism; Palestine-Israel conflict; environmentalism, globalisation and human rights; rise and importance of India in world politics. **संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख मुद्दे** — विदेश नीति: अवधारणा और निर्धारक तत्व; विश्व शांति और शस्त्र-नियंत्रण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका; अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद; फ़िलिस्तीन-इज़राइल संघर्ष; पर्यावरणवाद, वैश्वीकरण और मानवाधिकार; विश्व राजनीति में भारत का उदय और महत्व।	Q.1(9), Q.1(10), Q.2(d), Q.2(e), Q.6

Books recommended in the syllabus (derive your answers from these) / पाठ्यक्रम में अनुशंसित पुस्तकें

Text books:

- Mahendra Kumar and Nandlal - Antarrashtriya Rajniti ke Saiddhantik Paksh (Shivlal Agarwal, Agra)
- B. L. Fadia - Antarrashtriya Rajniti ke Saiddhantik Paksh (Sahitya Bhawan, Agra)
- U. R. Ghai - Antarrashtriya Rajniti: Siddhant evam Vyavahar (Academic Publishing Company)

Reference books:

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- Hans J. Morgenthau - Politics Among Nations
- K. J. Holsti - International Politics: A Framework for Analysis
- Paul Kennedy - Preparing for the Twenty-First Century; John Gray - False Dawn

Always use the latest edition. Model answers in this paper follow the standard university textbooks listed above, in simplified exam-ready form. / नवीनतम संस्करण का प्रयोग करें।

Important advice / ज़रूरी सलाह

This is a **DEMO SAMPLE**. Its questions were chosen to show the style and standard of the answers; they are not from the actual sets. Do not depend on any sample paper alone: prepare the complete syllabus from your text book and use this paper to practise writing and time management.

यह एक **डेमो नमूना** है। इसके प्रश्न उत्तरों की शैली और स्तर दिखाने के लिए चुने गए हैं; ये वास्तविक सेटों के प्रश्न नहीं हैं। केवल किसी नमूना पेपर पर निर्भर न रहें: अपनी पाठ्यपुस्तक से पूरा पाठ्यक्रम तैयार करें और इस पेपर का उपयोग लेखन-अभ्यास व समय-प्रबंधन के लिए करें।

ONLINE STUDENT SEVA · PARIKSHA PASS

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

PART – I : English Medium – Model Answers

Every answer is written to the marks allotted — learn the structure, then write in your own words.

Section A · Q.1 : Answer key

No.	Ans.	Correct option	Explanation
1	(b)	Joseph Nye	Joseph S. Nye Jr. introduced the idea of soft power (the power of attraction) in his 1990 book Bound to Lead.
2	(c)	nation-state system	The treaties of 1648 recognised sovereign, territorial states, so scholars treat them as the origin of the modern state system.
3	(d)	international non-governmental organisation (a non-state actor)	Amnesty International is a human-rights NGO that works across borders and is not a government, so it is a non-state actor.
4	(a)	anti-ballistic missile defence systems	The ABM Treaty (signed 26 May 1972) restricted missile-defence systems so that neither side could hope to escape retaliation.
5	(b)	Second-strike capability	Second-strike capability makes deterrence credible because an attacker knows it will still face a devastating reply.
6	(b)	1 January 1967	The NPT recognises five such states (the United States, Russia as successor to the USSR, the United Kingdom, France and China) because they tested before 1 January 1967. The treaty was opened for signature on 1 July 1968 and entered into force in 1970.
7	(d)	Fulton, Missouri (USA)	Churchill spoke at Westminster College, Fulton, Missouri on 5 March 1946 and warned that an 'iron curtain' had descended across Europe.
8	(a)	Soviet bloc (the USSR and its allies)	COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) coordinated the economies of the Soviet bloc as a counterpart to the Marshall Plan; it was dissolved in 1991.
9	(b)	Rome Statute (1998)	The Rome Statute was adopted in July 1998 and came into force on 1 July 2002; the ICC sits at The Hague.
10	(c)	2005 World Summit	Paragraphs 138-139 of the 2005 World Summit Outcome Document accepted that each state must protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.

Section A · Q.2 : Short answers

Q.2(a) — 5 marks · ≈ 150–170 words

Write a short note on the Peace of Westphalia (1648).

The Peace of Westphalia (1648) is the name given to the treaties of Münster and Osnabrück that ended the Thirty Years' War in Europe.

- **Sovereignty:** each ruler became supreme inside his own territory, free from interference by the Pope or the Holy Roman Emperor.
- **Territorial state:** rulers accepted each other's borders and treated one another as legally equal, whatever their size.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **Non-intervention:** meddling in another state's internal affairs came to be seen as illegitimate.
- **Balance:** it encouraged a rough balance among European powers instead of one universal authority.

Significance: scholars treat 1648 as the starting point of the modern state system, which is why it is often called the 'Westphalian system'. Realists use it to argue that sovereign states are the main actors of world politics, while critics point out that globalisation and non-state actors now challenge it.

Q.2(b) 5 marks · ≈ 150–170 words

What is the 'security dilemma'? Explain with an example.

The **security dilemma** is a situation in which steps taken by one state to increase its own security make other states feel less secure, so that all end up less safe. The idea is associated with John Herz (1950) and Herbert Butterfield.

- **Uncertainty:** in an anarchic world no state can be sure of another's intentions, so defensive steps look like preparation for attack.
- **Reaction:** the neighbour answers with its own build-up, and a spiral of mutual suspicion follows.
- **Result:** both sides spend more and are more fearful, though neither wanted war.

Example: the arms race between the USA and the USSR in the Cold War. Each new missile system, built for 'defence', pushed the rival to build more, until both held thousands of warheads.

Way out: confidence-building measures, transparency and arms-control treaties reduce the dilemma, because they make intentions easier to read.

Q.2(c) 5 marks · ≈ 150–170 words

Write a short note on Churchill's 'Iron Curtain' speech (1946).

Winston Churchill, then out of office as British Prime Minister, delivered the speech on 5 March 1946 at Westminster College, Fulton, Missouri, with US President Truman present.

- **Central image:** he said that 'from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the Continent', dividing Eastern Europe, under Soviet influence, from the West.
- **Warning:** he accused the Soviet Union of spreading communist control and urged a close 'special relationship' between Britain and the USA to counter it.
- **Reaction:** Moscow condemned the speech, and Stalin compared Churchill to a warmonger.

Significance: the phrase became shorthand for the division of Europe. The speech is seen as an early public marker of the Cold War, a year before the Truman Doctrine (1947) set out the policy of containment.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Q.2(d) 5 marks · ≈ 150–170 words

Distinguish between peacekeeping and peace enforcement in the work of the United Nations.

Basis	Peacekeeping	Peace enforcement
Consent	Needs the consent of the parties to the conflict	Does not need the consent of the parties
Force	Light arms; force only in self-defence or to defend the mandate	Military force may be used to compel compliance
Role	Neutral and impartial; monitors cease-fires and buffer zones	Takes sides against an aggressor to restore peace
Legal basis	Mandate of the Security Council, usually under Chapter VI (and VII for robust missions)	Security Council authorisation under Chapter VII of the Charter
Example	UN missions in Cyprus and Lebanon	Korea (1950) and Kuwait (1991) coalitions authorised by the Council

Peacekeeping is not mentioned in the Charter as such; it grew out of practice, beginning with UN observers in 1948. India has been one of the largest contributors of troops to UN missions.

Q.2(e) 5 marks · ≈ 150–170 words

What is the 'two-state solution' in the Palestine-Israel conflict? State the main issues on which it is stuck.

The **two-state solution** proposes an independent State of Palestine living side by side with Israel in peace and security. It rests on UN General Assembly Resolution 181 (1947), which proposed partition, and on the Oslo Accords (1993), which began a negotiated process. India supports this solution.

The final-status issues that have blocked agreement are:

1. **Borders:** whether a Palestinian state should be based on the pre-1967 lines, with agreed land swaps.
2. **Jerusalem:** both sides claim the city as their capital and have sacred sites there.
3. **Refugees:** the status and possible return or compensation of Palestinian refugees.
4. **Settlements:** the growth of Israeli settlements in the West Bank.
5. **Security:** Israel's security guarantees and the control of Gaza and the West Bank.

Section B : Long answers

Q.3 · Unit 1 10 marks · ≈ 600–700 words

Explain the concepts of hard power, soft power and smart power. How do they influence a state's position in international politics?

INTRODUCTION

Power is the central concept of international politics: a state's power decides how far it can protect its interest and shape the choices of others. Traditionally power meant military and economic

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

strength. In 1990 Joseph S. Nye Jr. (Bound to Lead; later Soft Power, 2004) added a second face of power, the ability to get what you want by attraction instead of force. This led to the three ideas of hard, soft and smart power.

HARD POWER

Hard power is the ability to make others act as you wish through **coercion or payment**.

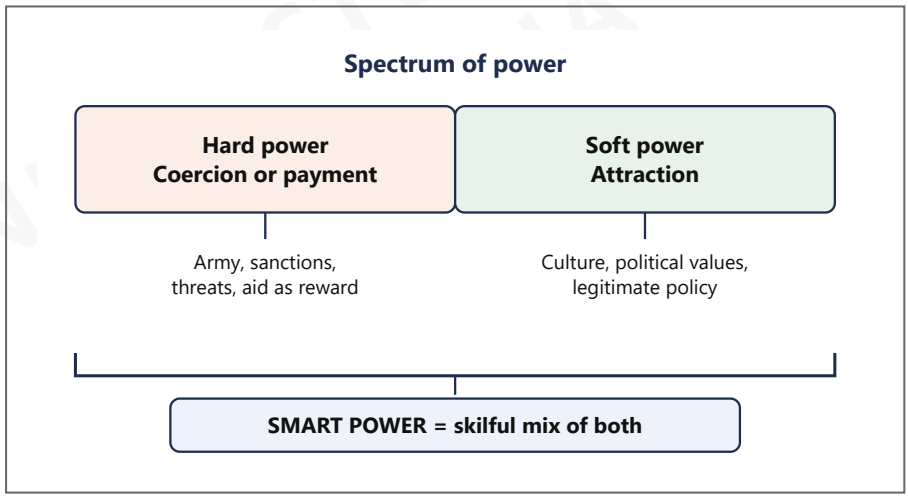
- **Instruments:** armed force, threats, military alliances, economic sanctions, tariffs and economic aid used as a reward.
- **Examples:** the US-led invasion of Iraq in 2003 and the Western sanctions on Russia after 2022.
- **Strength:** results are quick and measurable. **Weakness:** it is costly, invites resentment and cannot easily change what people believe.

SOFT POWER

Soft power is the ability to **shape the preferences of others through attraction**, so that they want what you want. Nye names three sources:

1. a country's **culture**, where it is attractive to others;
2. its **political values**, when it lives up to them at home and abroad;
3. its **foreign policies**, when others see them as legitimate and morally credible.

Examples are Hollywood and universities in the USA, the Korean wave, and Japanese popular culture. India's soft power rests on yoga (the UN General Assembly adopted 21 June as the International Day of Yoga in 2014), Bollywood, cuisine, Buddhist heritage, its democratic record, and development programmes such as ITEC and the work of the Indian Council for Cultural Relations.



Spectrum of power: from coercion (hard) to attraction (soft); smart power combines both

SMART POWER

Smart power is the **skilful combination** of hard and soft power so that they reinforce each other. The term was popularised by Nye and Richard Armitage through the CSIS Commission on Smart Power (2007) and was used in US diplomacy from 2009. A state using smart power may keep a strong defence, yet rely on alliances, aid, diplomacy and cultural exchange to win support.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

COMPARISON

Basis	Hard power	Soft power	Smart power
Nature	Coercion or payment	Attraction and persuasion	Mix of both
Instruments	Army, sanctions, aid	Culture, values, policy, media	Choice of tool as the situation needs
Speed and cost	Fast but costly	Slow and cheap	Balanced
Effect on others	Compliance, sometimes resentment	Willing cooperation	Compliance and goodwill
Example	Military action	Yoga diplomacy	Alliances plus development aid and diplomacy

INFLUENCE ON A STATE'S POSITION

- **Legitimacy and agenda-setting:** a state admired by others finds it easier to set the agenda and win votes in international bodies.
- **Alliances and coalitions:** attraction brings partners without the cost of pressure.
- **Economic gains:** a good image attracts students, tourists, investment and trade.
- **Crisis behaviour:** in a crisis hard power gives the last word, but soft power decides whether others will stand behind the state.
- **Limits of soft power:** it is hard to measure, governments do not fully control it because civil society and media produce much of it, and it can be damaged by policy. Many observers hold that the Iraq war reduced American soft power.

CRITICISM

Realists treat soft power as secondary, since material strength finally decides outcomes. Others warn that the idea can be misused for propaganda, and in 2017 a US think-tank coined the term 'sharp power' for authoritarian efforts to manipulate foreign opinion.

CONTEMPORARY ILLUSTRATION

China combines economic and military strength with the Belt and Road Initiative (launched in 2013) and cultural outreach such as Confucius Institutes, so that its influence rests on both kinds of power. India's Vaccine Maitri programme of 2021, in which COVID-19 vaccines were supplied to many countries, is often cited as an effort to build goodwill and show responsibility. In every such case the real test of soft power is whether the attraction survives when the state's actions at home and abroad do not match its words.

CONCLUSION

Modern states need both kinds of power. Hard power secures the state, while soft power makes its security lasting and its leadership acceptable. India's rise as a power rests on both: a growing economy and military on one side, and democratic legitimacy and cultural reach on the other.

Q.3 (OR) · Unit 1 — 10 marks · ≈ 600–700 words

Explain Neo-realism (Structural Realism) of Kenneth Waltz. How does it differ from classical

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

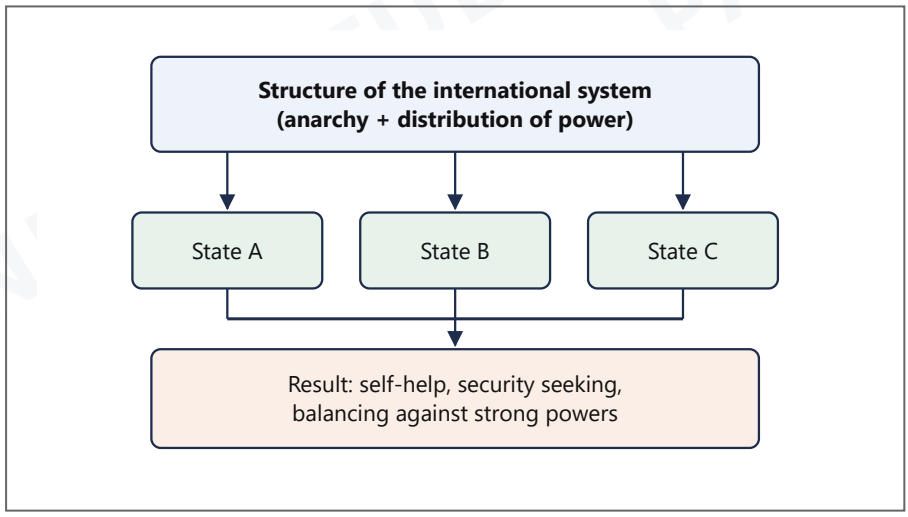
Realism, and what are its limitations?

INTRODUCTION

Neo-realism, also called Structural Realism, was developed by the American scholar **Kenneth N. Waltz** in his book *Theory of International Politics* (1979). Waltz accepted the realist belief that states are the main actors and seek security, but he changed the explanation. For him, state behaviour is shaped not mainly by human nature but by the **structure of the international system**.

MAIN IDEAS OF WALTZ

1. **Anarchy:** the international system has no world government above states. Every state must depend on self-help for its survival.
2. **Structure:** the system is defined by (a) its ordering principle, which is anarchy, (b) the sameness of its units, since all states perform similar functions of defence and survival, and (c) the **distribution of capabilities**, meaning how many great powers exist.
3. **States as security seekers:** states want to survive and so aim at a safe level of power, not unlimited power. This view is known as *defensive realism*.
4. **Balance of power as an outcome:** states may not plan it, yet balancing happens automatically because weaker states join together against a rising power.
5. **Polarity:** Waltz argued that a **bipolar** system, like the Cold War, is more stable than a multipolar one, because two powers can judge each other more clearly and miscalculation is less likely.



Neo-realism: the structure of the system (anarchy and distribution of power) shapes the behaviour of states

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

DIFFERENCE FROM CLASSICAL REALISM

Basis	Classical Realism (Morgenthau)	Neo-realism (Waltz)
Main book	Politics Among Nations (1948)	Theory of International Politics (1979)
Cause of conflict	Human nature and the desire for power	Anarchic structure of the system
Power	An end in itself	A means to survival
Level of analysis	Individual and state	System as a whole
Method	Historical and philosophical	Scientific and theory-building
Approach to behaviour	Leaders' choices matter	Structure limits choices

OFFENSIVE AND DEFENSIVE BRANCHES

John Mearsheimer, in *The Tragedy of Great Power Politics* (2001), developed **offensive realism**. He argued that because states can never be sure of others' intentions, great powers try to gain as much power as possible, and the best way to survive is to become the regional hegemon. Waltz, by contrast, held that too much power only provokes counter-balancing.

LIMITATIONS AND CRITICISM

- **Cannot explain change:** critics say neo-realism failed to predict or explain the peaceful end of the Cold War, because it assumed that the structure was stable.
- **Ignores domestic politics:** the nature of a regime, public opinion and leadership are left out.
- **Too state-centric:** it gives little space to international institutions, multinational companies and non-state actors.
- **Neglects cooperation:** liberal institutionalists such as Robert Keohane argue that institutions can reduce the effects of anarchy.
- **Static and abstract:** constructivists such as Alexander Wendt hold that anarchy is not fixed, since 'anarchy is what states make of it'.

RELEVANCE TODAY

Neo-realists explain the present rivalry between the United States and China as a result of a shift in the distribution of power, as the world moves from unipolarity towards multipolarity. They read groupings such as the Quad (Australia, India, Japan and the US), revived at leaders' level in 2021, as an example of balancing. Critics reply that deep economic interdependence and domestic politics also shape these choices, which a purely structural theory cannot capture, so most scholars now use neo-realism together with other approaches.

CONCLUSION

Neo-realism made the realist tradition more scientific by moving attention from human nature to the structure of the international system. It remains a major tool for explaining great power rivalry, alliance formation and balancing, but it is incomplete without the study of domestic politics, institutions and ideas.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Q.4 · Unit 2 10 marks · ≈ 600–700 words

Explain the theory of nuclear deterrence and Mutually Assured Destruction (MAD). What are its conditions and criticisms?

INTRODUCTION

Deterrence means preventing an opponent from taking an action by making it clear that the cost will be greater than the gain. After the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, and especially after the Soviet Union tested its own bomb in 1949, deterrence became the main idea of strategic thinking. It rests on the belief that nuclear weapons are useful mainly to **prevent war**, not to fight it.

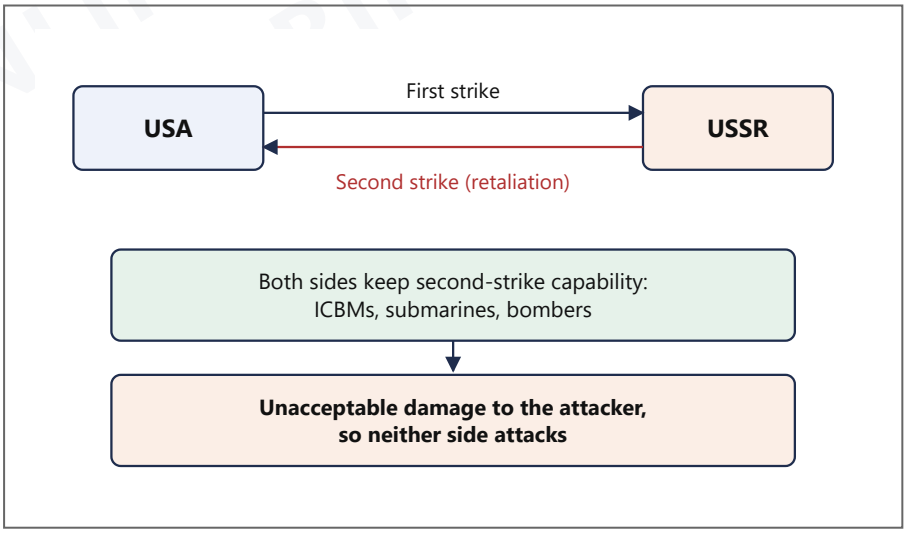
TYPES OF DETERRENCE

1. **Deterrence by punishment:** the threat of massive retaliation after an attack.
2. **Deterrence by denial:** the ability to defeat the attack itself, for example by missile defence.
3. **Extended deterrence:** a nuclear power promises protection to its allies. The US 'nuclear umbrella' over NATO members is the standard example.

MUTUALLY ASSURED DESTRUCTION (MAD)

By the 1960s both superpowers had so many weapons that **each could destroy the other even after being hit first**. This condition, named MAD in the early 1960s, meant that a first strike would be suicidal. Peace was therefore kept by mutual fear. Its key element is **second-strike capability**, the ability to survive a surprise attack and still strike back with unacceptable damage. This was ensured by the **nuclear triad**:

- land-based intercontinental ballistic missiles (ICBMs) in hardened silos;
- submarine-launched ballistic missiles (SLBMs), which are hard to find;
- long-range strategic bombers.



Logic of deterrence: a first strike invites a devastating second strike, so neither side attacks

CONDITIONS FOR DETERRENCE TO WORK

- **Capability:** enough weapons that survive a first strike.
- **Credibility:** the opponent must believe that the threat will really be carried out.
- **Communication:** the threat must be clearly understood by the other side.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **Rationality:** both leaders must weigh costs and act in their own survival interest.
- **Secure command and control:** to avoid accidental or unauthorised launch.

ROLE IN THE COLD WAR

Deterrence is often credited with preventing direct war between the United States and the Soviet Union, even in crises such as the Cuban Missile Crisis of 1962. The **ABM Treaty (1972)** strictly limited missile defence so that neither side could weaken the other's second strike, thereby protecting the balance of terror. India follows a doctrine of **credible minimum deterrence** with a **no-first-use** policy; its draft doctrine was released in August 1999 and the Cabinet Committee on Security reviewed and adopted it in January 2003.

CRITICISMS

- **Rationality cannot be guaranteed:** leaders may misjudge, or may be driven by ideology or panic.
- **Risk of accident:** a false warning can nearly cause disaster. On 26 September 1983 Soviet officer Stanislav Petrov judged a satellite alert of incoming missiles to be a false alarm and did not escalate.
- **Arms race:** the need to keep a secure second strike encourages the build-up of weapons.
- **Stability-instability paradox:** nuclear stability at the top may encourage smaller conventional or proxy conflicts below it.
- **Moral objection:** it rests on the threat of mass killing of civilians, which many consider unethical.
- **Weak against non-state actors:** terrorists cannot be threatened with retaliation in the same way.

DETERRENCE IN SOUTH ASIA

India conducted its Pokhran-II tests on 11 and 13 May 1998, and Pakistan followed with tests at Chagai on 28 and 30 May 1998. Some scholars argue that nuclear weapons have helped to keep India-Pakistan conflicts limited, as in the Kargil conflict of 1999, while others point out that the 2001-02 military stand-off and repeated crises show how close the region has come to danger. The debate shows that the same theory can be read both as a reason for optimism and as a warning.

CONCLUSION

Nuclear deterrence has helped to avoid a third world war among nuclear powers, but it depends on rational leaders, reliable systems and good luck. For this reason, supporters of disarmament continue to press for treaties that reduce, and finally remove, the weapons on which deterrence rests.

Q.4 (OR) · Unit 2 — 10 marks · ≈ 600–700 words

Discuss the major US-Soviet (US-Russian) arms control agreements: SALT, the INF Treaty and START. How far did they succeed?

INTRODUCTION

Arms control means agreed limits on the number, type or deployment of weapons, without necessarily abolishing them. It is different from disarmament, which aims at reducing or

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

eliminating weapons. After the Cuban Missile Crisis of 1962 both superpowers saw the need to manage their rivalry, and a series of bilateral agreements followed.

1. SALT I AND THE ABM TREATY (1972)

The Strategic Arms Limitation Talks began in 1969. On **26 May 1972**, in Moscow, US President Richard Nixon and Soviet leader Leonid Brezhnev signed:

- the **ABM Treaty**, which limited each side to a very small missile-defence system, so that neither could hope to defend itself against a retaliatory strike;
- an **Interim Agreement** that froze the number of strategic ballistic-missile launchers for five years.

SALT I did not reduce weapons, but it accepted the idea of parity and mutual vulnerability.

2. SALT II (1979)

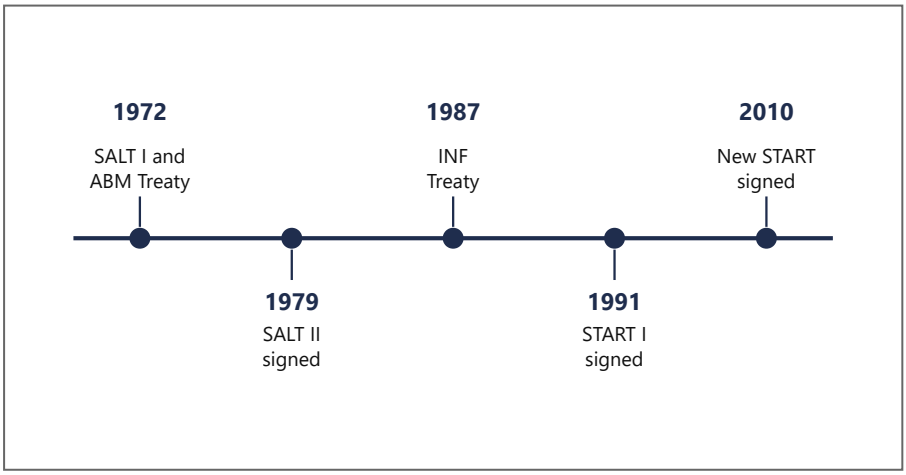
Signed on **18 June 1979** in Vienna by Jimmy Carter and Brezhnev, SALT II set equal overall ceilings on strategic launchers and placed limits on multiple warheads (MIRVs). After the Soviet invasion of Afghanistan in December 1979 the US Senate did not ratify it, although both sides said they would broadly observe its limits for some time.

3. INF TREATY (1987)

Signed on **8 December 1987** in Washington by Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev, it entered into force in 1988. It banned all **ground-launched ballistic and cruise missiles with ranges between 500 and 5,500 km**. It was the first treaty to eliminate a whole class of nuclear missiles, and about 2,700 missiles were destroyed by 1991. It also provided for on-site inspection, a major step in verification. The United States withdrew from the treaty in August 2019 after accusing Russia of violating it, which Russia denied.

4. START I (1991) AND NEW START (2010)

- **START I** was signed on 31 July 1991 by George H. W. Bush and Gorbachev, and entered into force in 1994. For the first time it **actually reduced** strategic warheads, setting a limit of about 6,000 on each side.
- **New START** was signed by Barack Obama and Dmitry Medvedev in Prague on 8 April 2010 and entered into force on 5 February 2011. It limited each side to 1,550 deployed warheads and 700 deployed launchers. In 2021 it was extended for five years.



Timeline of US-Soviet/Russian arms control agreements, 1972 to 2010

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

ASSESSMENT

Successes

- Reduced the risk of accidental war and built trust through talks and inspections.
- The INF and START treaties cut real numbers of weapons.
- Verification methods such as satellite monitoring and on-site checks became accepted practice.

Limitations

- Early treaties only capped numbers and left room for modernisation and for new weapons, so the arms race went on in other forms.
- Agreements depend on political relations; withdrawals and non-ratification show their fragility.
- Only two powers were involved, while other nuclear states, including China, were outside the treaties.
- New technologies such as hypersonic and space weapons are not fully covered.

WHY VERIFICATION MATTERS

At the signing of the INF Treaty, President Reagan used the Russian proverb 'trust, but verify'. The treaty's inspection system, with teams visiting each other's missile bases and factories, showed that agreements need checking as well as promises. Without trusted verification, each side suspects the other of cheating, which weakens the treaty and invites withdrawal. This is why modern disarmament proposals, such as those for fissile-material control, place so much stress on transparent and impartial monitoring.

CONCLUSION

Arms control did not end the nuclear threat, but it made the superpower competition more predictable and, in the case of INF and START, reduced actual arsenals. Its experience shows that lasting limits need both political trust and strong verification.

Q.5 · Unit 3 — 10 marks · ≈ 600–700 words

Describe the Cuban Missile Crisis of 1962: its background, main events, resolution and importance in the Cold War.

INTRODUCTION

The Cuban Missile Crisis of October 1962 was the most dangerous moment of the Cold War, when the United States and the Soviet Union came closest to a nuclear war. It lasted thirteen days, from 16 to 28 October 1962.

BACKGROUND

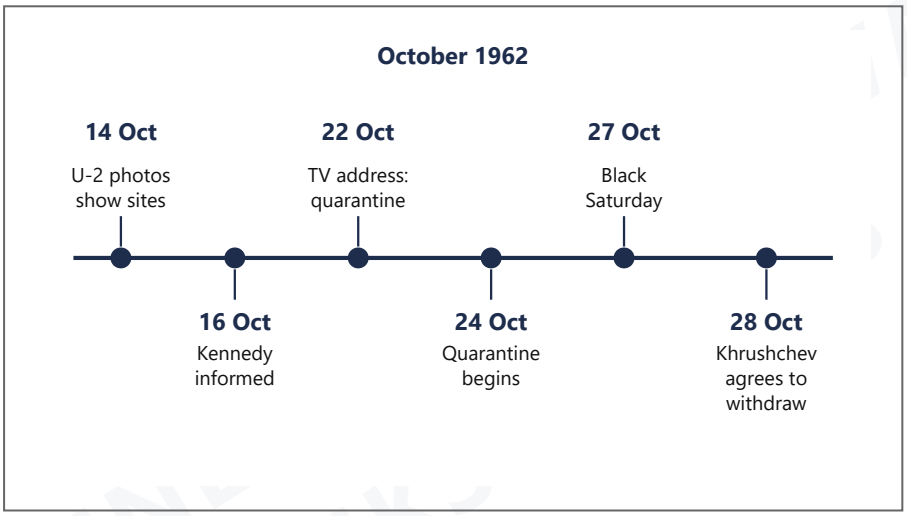
- **Cuban Revolution:** Fidel Castro took power in 1959 and moved closer to the Soviet Union. The US broke relations in January 1961.
- **Bay of Pigs (April 1961):** a US-backed invasion by Cuban exiles failed, which convinced Castro that another attack would come.
- **Missile gap in Europe:** the US had placed Jupiter missiles in Turkey and Italy, within range of Soviet territory. Soviet leader Nikita Khrushchev saw a chance to correct the balance.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **Soviet plan:** in 1962 the USSR secretly began placing medium-range nuclear missiles in Cuba, only about 90 miles from Florida, to defend Cuba and to improve its own strategic position.

MAIN EVENTS

Date (1962)	Event
14 Oct	A US U-2 spy plane photographs missile sites under construction
16 Oct	President John F. Kennedy is shown the evidence and forms the ExComm advisory group
22 Oct	Kennedy announces on television a naval 'quarantine' of Cuba
24 Oct	The quarantine takes effect; Soviet ships approach and then turn back
26-27 Oct	Khrushchev sends two messages; on 27 Oct, known as 'Black Saturday', a US U-2 is shot down over Cuba
28 Oct	Khrushchev announces that the missiles will be dismantled



Timeline of the Cuban Missile Crisis, 14 to 28 October 1962

The word 'quarantine' was chosen instead of 'blockade' because a blockade is an act of war in international law. Kennedy rejected an immediate air strike or invasion, which his military advisers had suggested, and chose a graded response that left Khrushchev room to retreat.

RESOLUTION

- The USSR agreed to **withdraw its missiles** from Cuba under UN verification.
- The US gave a public pledge **not to invade Cuba**.
- In a secret understanding, the US also agreed to **remove its Jupiter missiles from Turkey**, which was done in the following months.

CONSEQUENCES AND IMPORTANCE

1. **Hotline:** in 1963 the two powers set up a direct Moscow-Washington communication link to avoid miscommunication.
2. **Arms control:** the Partial Test Ban Treaty (August 1963) banned nuclear tests in the atmosphere, in space and under water.
3. **Beginning of detente:** both leaders learned the danger of brinkmanship, and relations began to move from confrontation towards managed rivalry.
4. **Political effects:** Khrushchev was seen as having backed down and was removed from power in October 1964; the Soviet Union later sought nuclear parity with the US. Castro's Cuba stayed

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

firmly in the Soviet camp.

5. **Lesson for crisis management:** it became the standard case study for deterrence, bargaining and decision-making theories.

LESSONS FOR DECISION-MAKING THEORY

Scholars have studied the crisis closely. Graham Allison's book *Essence of Decision* (1971) used it to compare three models: the **rational actor** model, in which each government acts as a single calculating unit; the **organisational process** model, in which routines of agencies shape action; and the **bureaucratic politics** model, in which bargaining among officials shapes the result. The crisis is therefore useful for understanding both how leaders make choices under pressure and why communication and time for reflection are essential.

CONCLUSION

The crisis showed that nuclear weapons made a direct clash between superpowers too dangerous to risk. It ended through careful diplomacy and compromise, and it pushed both sides towards communication and arms control, so it is rightly seen as a turning point in Cold War history.

Q.5 (OR) · Unit 3 — 10 marks · ≈ 600–700 words

Explain the origin, principles and role of the Non-Aligned Movement (NAM). Is it still relevant after the end of the Cold War?

INTRODUCTION

The Non-Aligned Movement (NAM) was a group of newly independent and developing countries that decided **not to join either the US-led or the Soviet-led military bloc** during the Cold War. Non-alignment does not mean neutrality or isolation. It means an independent foreign policy, with freedom to judge each issue on its merits.

ORIGIN

- **Background:** after 1945 many colonies became free in Asia and Africa. They wished to protect their freedom and use their resources for development, not to become pawns in superpower rivalry.
- **Bandung Conference (April 1955):** 29 Asian and African countries met in Indonesia and declared principles of peace, equality and anti-colonialism, which prepared the ground for NAM.
- **Founders:** Jawaharlal Nehru (India), Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Egypt), Sukarno (Indonesia) and Kwame Nkrumah (Ghana).
- **First summit:** held at **Belgrade from 1 to 6 September 1961**, attended by 25 member countries.

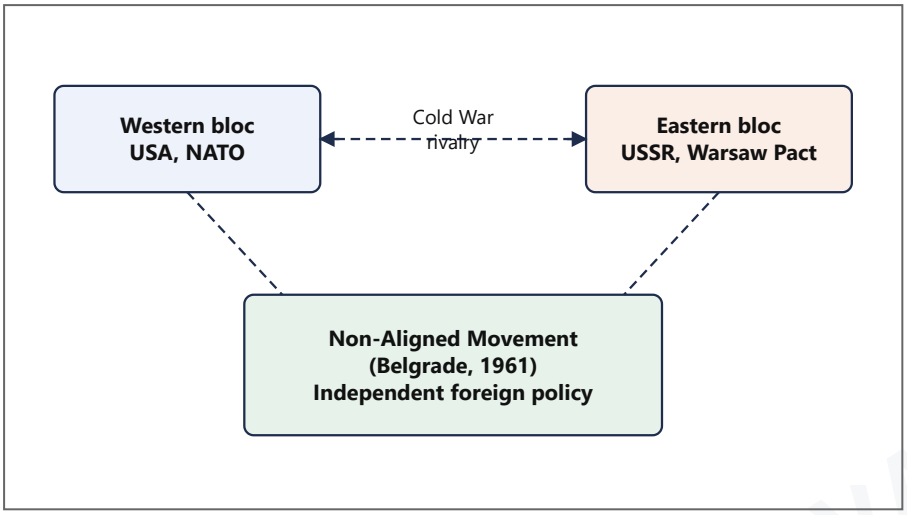
PRINCIPLES

The movement drew on the Panchsheel (1954) and the Bandung principles:

1. respect for sovereignty and territorial integrity of all nations;
2. non-aggression and non-interference in internal affairs;
3. equality of all races and nations;
4. peaceful settlement of disputes and peaceful coexistence;

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

5. no membership of military alliances of the great powers, and no foreign bases on one's soil in the interest of those powers;
6. opposition to colonialism, racism and apartheid.



Three blocs in the Cold War world: the Western bloc, the Eastern bloc and the non-aligned countries

ROLE AND ACHIEVEMENTS

- **Reduced Cold War tension:** NAM gave a third voice that urged talks, disarmament and peaceful settlement; it opposed the arms race and supported nuclear disarmament.
- **Decolonisation:** it supported liberation movements in Africa and Asia and campaigned strongly against apartheid in South Africa.
- **Economic demands:** it pressed for a **New International Economic Order** in the 1970s, along with the G-77 group, seeking fairer trade and aid for developing countries.
- **Voice in the UN:** by acting together, members gave the developing world a large share of votes in the General Assembly.
- **India's role:** India was a founder and later hosted the 7th summit at New Delhi in 1983 under Indira Gandhi.

WEAKNESSES

Members had different interests and sometimes sided with one bloc, for example, India's 1971 treaty with the USSR drew some criticism. Disputes between members such as Iran and Iraq weakened unity, and NAM had no armed force or enforcement power. It also lacked a permanent secretariat.

RELEVANCE AFTER THE COLD WAR

Critics ask what NAM stands for when there are no longer two blocs. Supporters reply that its purposes remain valid:

- **Unfinished agenda:** poverty, unequal trade, climate justice and reform of the UN Security Council.
- **Multi-polar world:** the idea of strategic autonomy is again popular, and India describes its current approach as 'multi-alignment' or strategic autonomy.
- **Collective voice:** NAM, with over 120 members, is still one of the largest groupings of states after the UN itself.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

INDIA'S PRACTICAL ROLE

Even before the Belgrade summit, India used its independent position to help in conflicts. After the Korean War, it chaired the Neutral Nations Repatriation Commission and sent a custodian force in 1953 to handle prisoners of war. In 1954 it chaired the international supervisory commission for Indochina set up by the Geneva Conference. These actions earned India respect as an honest broker and showed that non-alignment could be a constructive policy and not a passive one.

CONCLUSION

NAM gave newly independent states a way to protect their sovereignty in a divided world. Its form has changed, but its core idea of an independent foreign policy and fair global order is still of value to developing nations.

Q.6 · Unit 4 — 10 marks · ≈ 600–700 words

Discuss the basic principles of India's foreign policy with special reference to Panchsheel, the Gujral Doctrine and the 'Neighbourhood First' policy.

INTRODUCTION

India's foreign policy took shape under Jawaharlal Nehru, who was both Prime Minister and Foreign Minister from 1947 to 1964. Its main aims are to protect national security and territorial integrity, to promote economic development, and to work for world peace. Its basic principles have remained fairly steady, although their form has changed with time.

BASIC PRINCIPLES

1. **Non-alignment and strategic autonomy:** freedom to decide each issue independently, without joining a power bloc.
2. **Peaceful coexistence and peaceful settlement of disputes.**
3. **Opposition to colonialism, racism and apartheid.**
4. **Support for the UN, international law and disarmament.**
5. **Friendly relations with neighbours** and a concern for development partnership.
6. **Cultural values:** the ancient idea of *Vasudhaiva Kutumbakam* (the world is one family) is often cited as a base of India's outlook.

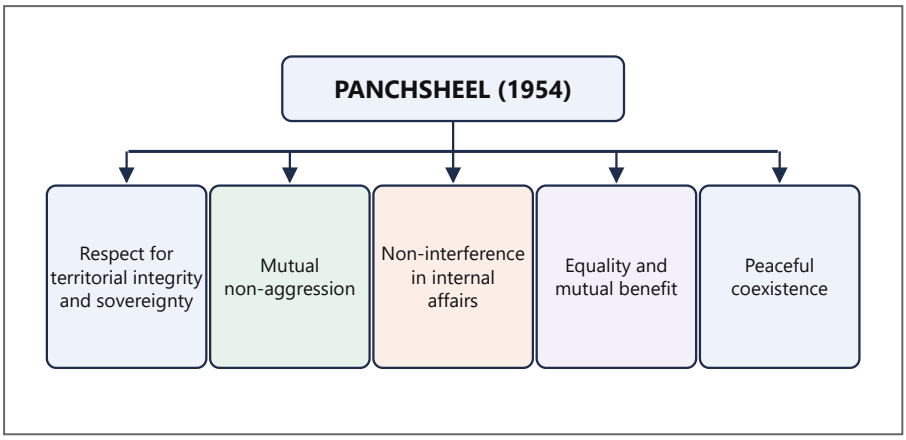
PANCHSHEEL (1954)

Panchsheel, the 'five principles of peaceful coexistence', was first formally stated in the **Agreement on Trade and Intercourse between the Tibet Region of China and India, signed on 29 April 1954**. They were repeated in the joint statement of Nehru and Zhou Enlai in June 1954. The five principles are:

1. mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty;
2. mutual non-aggression;
3. mutual non-interference in each other's internal affairs;
4. equality and mutual benefit;
5. peaceful coexistence.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

They became the moral base of NAM and were included in the Bandung Declaration of 1955. However, the 1962 India-China war showed the limits of relying on principles alone, and India afterwards gave more weight to defence preparedness.



The five principles of Panchsheel (1954)

GUJRAL DOCTRINE (1996-97)

I. K. Gujral, as External Affairs Minister and then Prime Minister, announced five principles for relations with neighbours:

1. India does not ask for **reciprocity** from smaller neighbours; it gives what it can in good faith.
2. No South Asian country should allow its territory to be used against the interest of another.
3. No country should interfere in the internal affairs of another.
4. All South Asian countries must respect each other's territorial integrity and sovereignty.
5. All disputes should be settled through peaceful **bilateral negotiations**.

Its achievements included the Ganga Water Treaty with Bangladesh (December 1996) and better ties with Nepal and Sri Lanka. Critics felt that giving without reciprocity could be misused by hostile states.

'NEIGHBOURHOOD FIRST' POLICY (2014 ONWARDS)

Announced after the 2014 swearing-in, to which leaders of the SAARC countries were invited, this policy stresses:

- **connectivity** through roads, rail, power grids and digital links;
- **trade and people-to-people contact**;
- **quick development assistance** and support in disasters, for example earthquake relief to Nepal in 2015;
- **regional groupings** such as BIMSTEC and the BBIN initiative, as SAARC has been slowed by India-Pakistan differences.

OTHER RECENT DIRECTIONS

The Look East Policy of 1991 became **Act East** in 2014. India now speaks of strategic autonomy and multi-alignment, working with several partners at once on trade, technology and security.

DETERMINANTS OF FOREIGN POLICY

Several factors shape these principles: **geography** (a long land and sea border and a position on the Indian Ocean), **history** (the colonial experience and the freedom struggle), **economic needs** (energy, trade and technology), **security concerns** (disputed borders and nuclear neighbours), **domestic politics**, and the **international environment**. The SAGAR vision of 2015, meaning

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Security and Growth for All in the Region, reflects the importance of the Indian Ocean, and shows how geography and economy together guide policy.

CONCLUSION

India's foreign policy combines idealism and realism. Panchsheel gave its moral language, the Gujral Doctrine its generosity towards neighbours, and Neighbourhood First its focus on connectivity and speed, all serving the national interest in a changing world.

Q.6 (OR) · Unit 4 — 10 marks · ≈ 600–700 words

Explain the UN's peacekeeping operations and the doctrine of the 'Responsibility to Protect' (R2P). Assess their successes and failures.

INTRODUCTION

The main purpose of the United Nations, set out in Article 1 of its Charter, is to maintain international peace and security. Besides the formal powers of the Security Council in Chapters VI and VII, the UN developed two important tools in practice: **peacekeeping**, from 1948, and the **Responsibility to Protect**, adopted in 2005.

UN PEACEKEEPING

Meaning: peacekeeping is the deployment of international military, police and civilian personnel, with the consent of the parties, to help maintain a ceasefire and support peace. The word is not in the Charter; because it lies between peaceful settlement (Chapter VI) and enforcement (Chapter VII), it is sometimes called 'Chapter six and a half'.

History: the first missions were UNTSO (1948, in the Middle East) and UNMOGIP (1949, India-Pakistan). The first armed force, **UNEF I**, was created in 1956 after the Suez crisis, largely through the efforts of Canada's Lester Pearson. UN peacekeepers received the **Nobel Peace Prize in 1988**.

Basic principles:

1. **Consent** of the main parties.
2. **Impartiality** towards all sides.
3. **Non-use of force** except in self-defence and defence of the mandate.

Evolution: after the Cold War the tasks widened from watching ceasefires to 'multidimensional' work such as supervising elections, disarming fighters, protecting civilians and rebuilding institutions, as set out in Boutros Boutros-Ghali's *An Agenda for Peace* (1992) and reviewed in the Brahimi Report (2000). India has been among the major troop contributors since the Korean War period, and Indian peacekeepers have served in many missions across Africa and elsewhere.

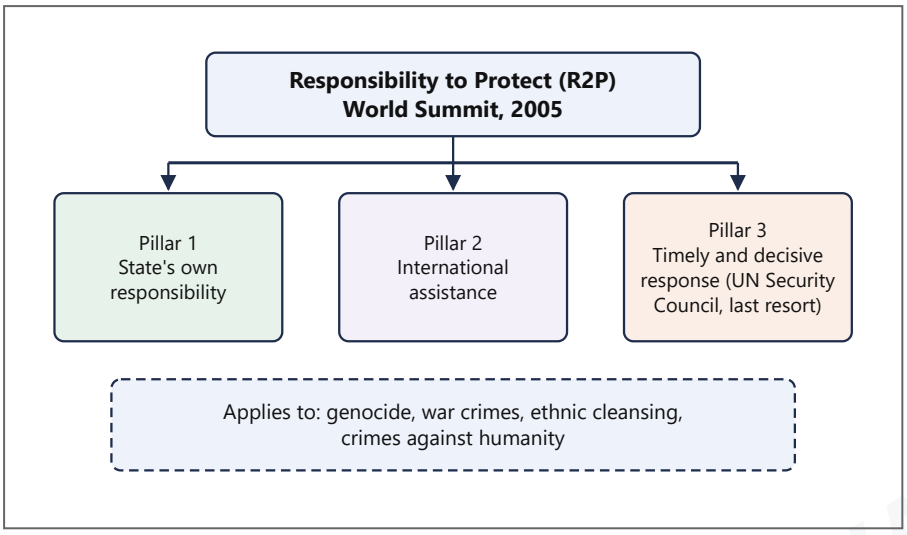
RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P)

After the failures in Rwanda and Kosovo, the question was when the world may act against mass atrocities within a state. The International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) proposed in 2001 that sovereignty carries a **responsibility**. The **2005 World Summit Outcome** (paragraphs 138-139) accepted R2P for four crimes: **genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity**. It rests on three pillars:

1. **The state's responsibility** to protect its own population.
2. **International assistance:** the world should help states to fulfil that duty.

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

3. **Timely and decisive response:** if a state manifestly fails, the international community may act through the Security Council, including with force as a last resort.



The three pillars of the Responsibility to Protect (2005)

SUCCESSES

- Many missions helped to end conflicts and supported elections and rebuilding, for example in Namibia (1989-90) and Cambodia (1992-93).
- Peacekeeping gives legitimacy and is cheaper than major wars.
- R2P put the protection of people on the international agenda and limited the old claim that atrocities are purely an internal matter.

FAILURES AND CRITICISMS

- **Rwanda (1994):** UN forces were small and had a limited mandate, and about 800,000 people were killed in a genocide.
- **Srebrenica (1995):** UN-declared 'safe area' fell, and more than 8,000 Bosnian Muslim men and boys were killed.
- **Dependence on great powers:** the veto in the Security Council can block action, as in Syria.
- **Selectivity and misuse:** after the NATO intervention in Libya in 2011, under Resolution 1973, critics said that R2P was used for regime change, and countries including India and Brazil urged more care.
- **Resource problems:** shortage of troops, funds and equipment, and cases of misconduct by peacekeepers.

REFORM OF PEACE OPERATIONS

After the failures of the 1990s, the Brahimi Report (2000) asked for clear and achievable mandates, better trained troops and faster deployment. A High-Level Independent Panel reviewed peace operations in 2015, and in 2018 the UN Secretary-General launched the 'Action for Peacekeeping' initiative to improve performance and safety. Troop-contributing countries like India have also asked that they be consulted before mandates are set, since their soldiers carry the risk on the ground.

CONCLUSION

Peacekeeping and R2P show the UN's ability to adapt, but their record is mixed, because both depend on the political will of member states, especially the permanent members of the Security

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Council. Reform of the Council and clear, realistic mandates are needed to make them more effective.

ONLINE STUDENT SEVA · PARIKSHA PASS

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

भाग – II : हिन्दी माध्यम – आदर्श उत्तर

प्रत्येक उत्तर अंक-भार के अनुसार लिखा गया है — ढाँचा सीखें, फिर अपने शब्दों में लिखें।

खण्ड – अ · प्रश्न 1 : उत्तर कुंजी

क्र.	उत्तर	सही विकल्प	स्पष्टीकरण
1	(b)	जोसेफ नाय	जोसेफ एस. नाय जूनियर ने अपनी 1990 की पुस्तक 'बाउंड टू लीड' में सॉफ्ट पावर (आकर्षण की शक्ति) की धारणा दी।
2	(c)	राष्ट्र-राज्य व्यवस्था	1648 की संधियों ने संप्रभु, भू-क्षेत्रीय राज्यों को मान्यता दी, इसलिए विद्वान इन्हें आधुनिक राज्य-व्यवस्था की शुरुआत मानते हैं।
3	(d)	अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (एक गैर-राज्य कर्ता)	एमनेस्टी इंटरनेशनल सीमाओं के पार काम करने वाला मानवाधिकार एन.जी.ओ. है, सरकार नहीं, इसलिए यह गैर-राज्य कर्ता है।
4	(a)	प्रक्षेपास्त्र-रोधी (एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल) रक्षा प्रणालियाँ	ए.बी.एम. संधि (26 मई 1972 को हस्ताक्षरित) ने मिसाइल-रक्षा प्रणालियाँ सीमित कीं ताकि कोई भी पक्ष जवाबी हमले से बचने की आशा न कर सके।
5	(b)	द्वितीय-प्रहार क्षमता	द्वितीय-प्रहार क्षमता निवारण को विश्वसनीय बनाती है, क्योंकि हमलावर जानता है कि उसे फिर भी विनाशकारी जवाब मिलेगा।
6	(b)	1 जनवरी 1967	NPT ऐसे पाँच राज्यों (अमेरिका, सोवियत संघ की उत्तराधिकारी रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन) को मान्यता देती है क्योंकि उन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परीक्षण किया था। संधि 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर के लिए खुली और 1970 में लागू हुई।
7	(d)	फुल्टन, मिसौरी (अमेरिका)	चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को वेस्टमिंस्टर कॉलेज, फुल्टन (मिसौरी) में बोलते हुए चेताया कि यूरोप में 'लौह आवरण' (आयरन कर्टेन) गिर गया है।
8	(a)	सोवियत गुट (सोवियत संघ और उसके सहयोगी)	कॉमेकॉन (पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद) ने मार्शल योजना के जवाब में सोवियत गुट की अर्थव्यवस्थाओं में तालमेल बैठाया; इसे 1991 में भंग कर दिया गया।
9	(b)	रोम संविधि (1998)	रोम संविधि जुलाई 1998 में अपनाई गई और 1 जुलाई 2002 से लागू हुई; आई.सी.सी. का मुख्यालय हेग में है।
10	(c)	2005 का विश्व शिखर सम्मेलन	2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के परिणाम-दस्तावेज़ के अनुच्छेद 138-139 ने स्वीकार किया कि हर राज्य को अपनी जनता को नरसंहार, युद्ध-अपराध, जातीय सफ़ाए और मानवता के विरुद्ध अपराधों से बचाना है।

खण्ड – अ · प्रश्न 2 : लघु उत्तर

प्रश्न 2(a) — **5 अंक · शब्द-सीमा ≈ 150–170 शब्द**

वेस्टफेलिया की संधि (1648) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

वेस्टफेलिया की संधि (1648) उन म्यूंस्टर और ओस्नाब्रुक संधियों का नाम है जिन्होंने यूरोप में तीस वर्षीय युद्ध को समाप्त किया।

- **संप्रभुता:** हर शासक अपने क्षेत्र में सर्वोच्च बन गया और पोप या पवित्र रोमन सम्राट के हस्तक्षेप से मुक्त हो गया।
- **भू-क्षेत्रीय राज्य:** शासकों ने एक-दूसरे की सीमाओं को माना और आकार चाहे जो हो, एक-दूसरे को कानूनी रूप से बराबर समझा।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **अहस्तक्षेप:** दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देना अनुचित माना जाने लगा।
- **संतुलन:** इसने किसी एक सार्वभौमिक सत्ता की जगह यूरोपीय शक्तियों के बीच मोटे तौर पर संतुलन को बढ़ावा दिया।

महत्व: विद्वान 1648 को आधुनिक राज्य-व्यवस्था की शुरुआत मानते हैं, इसीलिए इसे 'वेस्टफेलियाई व्यवस्था' कहा जाता है। यथार्थवादी इसी आधार पर कहते हैं कि संप्रभु राज्य ही विश्व राजनीति के मुख्य कर्ता हैं, जबकि आलोचक बताते हैं कि भूमंडलीकरण और गैर-राज्य कर्ता अब इस धारणा को चुनौती देते हैं।

प्रश्न 2(b) — **5 अंक · शब्द-सीमा ≈ 150–170 शब्द**

'सुरक्षा दुविधा' (सिक्योरिटी डिलेमा) क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।

सुरक्षा दुविधा वह स्थिति है जिसमें एक राज्य अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो कदम उठाता है, उससे दूसरे राज्य असुरक्षित महसूस करते हैं, और अंत में सभी कम सुरक्षित रह जाते हैं। यह विचार जॉन हर्ज़ (1950) और हर्बर्ट बटरफ़ील्ड से जुड़ा है।

- **अनिश्चितता:** अराजक विश्व में कोई राज्य दूसरे के इरादे नहीं जान सकता, इसलिए रक्षात्मक कदम भी हमले की तैयारी जैसे दिखते हैं।
- **प्रतिक्रिया:** पड़ोसी भी अपनी सैन्य तैयारी बढ़ाता है और आपसी संदेह का चक्र चल पड़ता है।
- **परिणाम:** दोनों पक्ष अधिक खर्च करते हैं और अधिक भयभीत रहते हैं, जबकि युद्ध कोई नहीं चाहता था।

उदाहरण: शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ की हथियारों की होड़। 'रक्षा' के नाम पर बनी हर नई मिसाइल प्रणाली ने प्रतिद्वंद्वी को और अधिक बनाने को प्रेरित किया, यहाँ तक कि दोनों के पास हज़ारों परमाणु हथियार हो गए।

समाधान: विश्वास-बहाली के उपाय, पारदर्शिता और शस्त्र-नियंत्रण संधियाँ इस दुविधा को घटाती हैं, क्योंकि इनसे इरादे समझना आसान हो जाता है।

प्रश्न 2(c) — **5 अंक · शब्द-सीमा ≈ 150–170 शब्द**

चर्चिल के 'आयरन कर्टेन' भाषण (1946) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद से हट चुके विंस्टन चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को फुल्टन (मिसौरी) के वेस्टमिंस्टर कॉलेज में यह भाषण दिया; अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन वहाँ मौजूद थे।

- **मुख्य बिंब:** उन्होंने कहा कि 'बाल्टिक के स्टेटिन से एड्रियाटिक के त्रिएस्ते तक महाद्वीप पर एक लौह आवरण (आयरन कर्टेन) गिर चुका है', जिसने सोवियत प्रभाव वाले पूर्वी यूरोप को पश्चिम से अलग कर दिया।
- **चेतावनी:** उन्होंने सोवियत संघ पर साम्यवादी नियंत्रण फैलाने का आरोप लगाया और इसके मुकाबले के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के घनिष्ठ 'विशेष संबंध' पर ज़ोर दिया।
- **प्रतिक्रिया:** मास्को ने भाषण की निंदा की और स्टालिन ने चर्चिल की तुलना युद्ध-भड़काने वाले से की।

महत्व: यह वाक्यांश यूरोप के विभाजन का प्रतीक बन गया। इस भाषण को शीत युद्ध का एक शुरुआती सार्वजनिक संकेत माना जाता है, जिसके एक वर्ष बाद ट्रूमैन सिद्धांत (1947) ने अवरोध (कंटेनमेंट) की नीति घोषित की।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रश्न 2(d) — 5 अंक · शब्द-सीमा ≈ 150–170 शब्द

संयुक्त राष्ट्र के कार्य में शांति-स्थापना (पीसकीपिंग) और शांति-प्रवर्तन (पीस एनफ़ोर्समेंट) में अंतर स्पष्ट कीजिए।

आधार	शांति-स्थापना (पीसकीपिंग)	शांति-प्रवर्तन (पीस एनफ़ोर्समेंट)
सहमति	संघर्ष के पक्षों की सहमति आवश्यक	पक्षों की सहमति आवश्यक नहीं
बल	हल्के हथियार; बल केवल आत्मरक्षा या जनादेश की रक्षा के लिए	पालन कराने के लिए सैन्य बल का प्रयोग हो सकता है
भूमिका	तटस्थ और निष्पक्ष; युद्ध-विराम और बफ़र क्षेत्रों की निगरानी	शांति बहाल करने के लिए हमलावर के विरुद्ध पक्ष लेता है
कानूनी आधार	सुरक्षा परिषद का जनादेश, प्रायः अध्याय VI के अंतर्गत (सशक्त मिशनों में अध्याय VII भी)	चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत सुरक्षा परिषद की अनुमति
उदाहरण	साइप्रस और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन	कोरिया (1950) और कुवैत (1991) के गठबंधन जिन्हें परिषद ने अधिकृत किया

शांति-स्थापना का चार्टर में इस नाम से उल्लेख नहीं है; यह व्यवहार से विकसित हुई, जिसकी शुरुआत 1948 में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों से हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैनिक भेजने वाले सबसे बड़े देशों में रहा है।

प्रश्न 2(e) — 5 अंक · शब्द-सीमा ≈ 150–170 शब्द

फ़लस्तीन-इज़राइल संघर्ष में 'द्वि-राष्ट्र समाधान' क्या है? उन मुख्य मुद्दों को बताइए जिन पर यह अटका है।

द्वि-राष्ट्र समाधान का प्रस्ताव है कि स्वतंत्र फ़लस्तीन राज्य इज़राइल के साथ शांति और सुरक्षा से साथ-साथ रहे। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 181 (1947), जिसमें विभाजन का सुझाव था, और ओस्लो समझौतों (1993) पर आधारित है, जिनसे बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत इसका समर्थन करता है।

अंतिम समझौते के जिन मुद्दों पर बात अटकी है, वे ये हैं:

1. **सीमाएँ:** क्या फ़लस्तीन राज्य 1967 से पहले की रेखाओं पर आधारित होगा, आपसी सहमति से भूमि-अदला-बदली के साथ।
2. **येरुशलम:** दोनों पक्ष इसे अपनी राजधानी मानते हैं और यहाँ दोनों के पवित्र स्थल हैं।
3. **शरणार्थी:** फ़लस्तीनी शरणार्थियों की स्थिति और उनकी संभावित वापसी या मुआवज़ा।
4. **बस्तियाँ:** पश्चिमी तट में इज़राइली बस्तियों का विस्तार।
5. **सुरक्षा:** इज़राइल की सुरक्षा की गारंटी तथा गाज़ा और पश्चिमी तट का नियंत्रण।

खण्ड – ब · दीर्घ उत्तर

प्रश्न 3 · इकाई 1 — 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

कठोर शक्ति (हार्ड पावर), मृदु शक्ति (सॉफ्ट पावर) और स्मार्ट शक्ति की अवधारणाओं को समझाइए।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

ये किसी राज्य की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं?

भूमिका

शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है: किसी राज्य की शक्ति तय करती है कि वह अपने हितों की कितनी रक्षा कर सकता है और दूसरों के निर्णयों को कितना प्रभावित कर सकता है। परंपरागत रूप से शक्ति का अर्थ सैन्य और आर्थिक ताकत था। 1990 में जोसेफ एस. नाय जूनियर (बाउंड टू लीड; बाद में सॉफ्ट पावर, 2004) ने शक्ति का दूसरा रूप जोड़ा, यानी बल की जगह आकर्षण से अपनी बात मनवाने की क्षमता। इसी से कठोर, मृदु और स्मार्ट शक्ति की तीन अवधारणाएँ निकलीं।

कठोर शक्ति (हार्ड पावर)

कठोर शक्ति वह क्षमता है जिससे **दबाव या भुगतान** द्वारा दूसरों से अपनी इच्छानुसार काम करवाया जाता है।

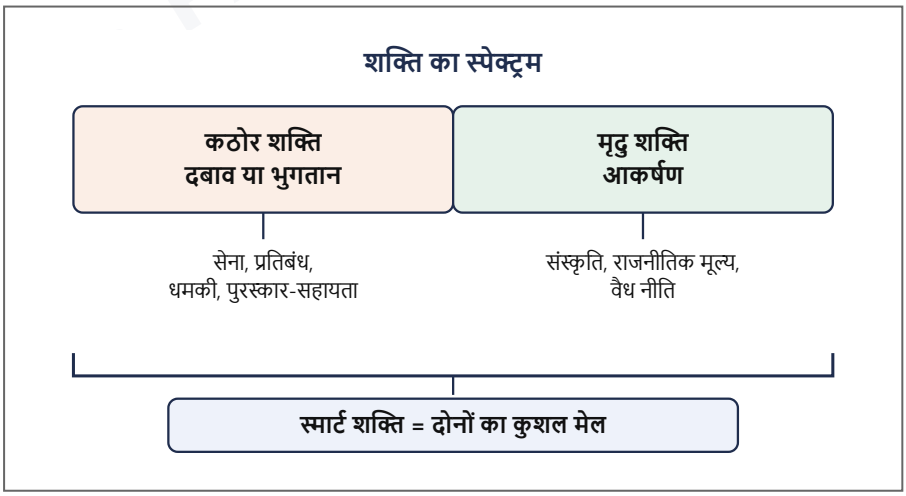
- **साधन:** सशस्त्र बल, धमकी, सैन्य गठबंधन, आर्थिक प्रतिबंध, शुल्क और पुरस्कार के रूप में दी गई आर्थिक सहायता।
- **उदाहरण:** 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर आक्रमण और 2022 के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध।
- **ताकत:** परिणाम तेज़ और मापने योग्य होते हैं। **कमज़ोरी:** यह महँगी है, नाराज़गी पैदा करती है और लोगों की सोच आसानी से नहीं बदल पाती।

मृदु शक्ति (सॉफ्ट पावर)

मृदु शक्ति वह क्षमता है जिससे **आकर्षण द्वारा दूसरों की पसंद को ढाला जाता है**, ताकि वे स्वयं वही चाहें जो आप चाहते हैं। नाय इसके तीन स्रोत बताते हैं:

1. देश की **संस्कृति**, जब वह दूसरों को आकर्षक लगे;
2. उसके **राजनीतिक मूल्य**, जब वह देश के भीतर और बाहर उन पर खरा उतरे;
3. उसकी **विदेश नीतियाँ**, जब दूसरे उन्हें वैध और नैतिक रूप से विश्वसनीय मानें।

उदाहरण हैं अमेरिका के हॉलीवुड और विश्वविद्यालय, कोरियाई लहर और जापान की लोकप्रिय संस्कृति। भारत की मृदु शक्ति योग (संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया), बॉलीवुड, खान-पान, बौद्ध विरासत, लोकतांत्रिक छवि तथा आई.टी.ई.सी. जैसे विकास कार्यक्रमों और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्य पर टिकी है।



शक्ति का स्पेक्ट्रम: दबाव (कठोर) से आकर्षण (मृदु) तक; स्मार्ट शक्ति दोनों को जोड़ती है

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

स्मार्ट शक्ति

स्मार्ट शक्ति कठोर और मृदु शक्ति का **कुशल मेल** है, ताकि दोनों एक-दूसरे को मज़बूत करें। यह शब्द नाय और रिचर्ड आर्मिटेज द्वारा सी.एस.आई.एस. आयोग (2007) के माध्यम से लोकप्रिय हुआ और 2009 से अमेरिकी कूटनीति में प्रयोग हुआ। स्मार्ट शक्ति अपनाने वाला राज्य मज़बूत रक्षा रखते हुए भी समर्थन जीतने के लिए गठबंधन, सहायता, कूटनीति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का सहारा लेता है।

तुलना

आधार	कठोर शक्ति	मृदु शक्ति	स्मार्ट शक्ति
स्वरूप	दबाव या भुगतान	आकर्षण और समझाना	दोनों का मेल
साधन	सेना, प्रतिबंध, सहायता	संस्कृति, मूल्य, नीति, मीडिया	स्थिति के अनुसार साधन का चयन
गति और लागत	तेज़ पर महँगी	धीमी पर सस्ती	संतुलित
दूसरों पर प्रभाव	अनुपालन, कभी-कभी नाराज़गी	स्वेच्छा से सहयोग	अनुपालन और सद्भावना
उदाहरण	सैन्य कार्रवाई	योग कूटनीति	गठबंधन के साथ विकास सहायता और कूटनीति

राज्य की स्थिति पर प्रभाव

- **वैधता और एजेंडा तय करना:** जिस राज्य की दूसरे सराहना करते हैं, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में एजेंडा तय करना और समर्थन जुटाना आसान होता है।
- **गठबंधन और गुट:** आकर्षण दबाव की लागत के बिना साझेदार जुटा देता है।
- **आर्थिक लाभ:** अच्छी छवि विद्यार्थियों, पर्यटकों, निवेश और व्यापार को खींचती है।
- **संकट में व्यवहार:** संकट में अंतिम शब्द कठोर शक्ति का रहता है, पर मृदु शक्ति तय करती है कि दूसरे राज्य के साथ खड़े होंगे या नहीं।
- **मृदु शक्ति की सीमाएँ:** इसे मापना कठिन है, सरकारें इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकतीं क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा नागरिक समाज और मीडिया रचते हैं, और नीतियों से यह घट सकती है। कई पर्यवेक्षक मानते हैं कि इराक युद्ध से अमेरिकी मृदु शक्ति घटी।

आलोचना

यथार्थवादी मृदु शक्ति को गौण मानते हैं क्योंकि अंततः भौतिक ताकत ही परिणाम तय करती है। कुछ लोग चेताते हैं कि इस विचार का प्रचार के लिए दुरुपयोग हो सकता है; 2017 में अमेरिका की एक शोध-संस्था ने विदेशी जनमत को प्रभावित करने के अधिनायकवादी प्रयासों के लिए 'शार्प पावर' शब्द गढ़ा।

समकालीन उदाहरण

चीन आर्थिक और सैन्य शक्ति को बेल्ट एंड रोड पहल (2013 में शुरू) और कन्फ्यूशियस संस्थानों जैसे सांस्कृतिक प्रयासों से जोड़ता है, इसलिए उसका प्रभाव दोनों प्रकार की शक्ति पर टिका है। भारत का 2021 का वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम, जिसमें कई देशों को कोविड-19 टीके दिए गए, सद्भावना बनाने और ज़िम्मेदार छवि दिखाने के प्रयास के रूप में अक्सर उद्धृत होता है। ऐसे हर मामले में मृदु शक्ति की असली परीक्षा यह है कि जब राज्य के देश के भीतर और बाहर के कार्य उसकी बातों से मेल न खाएँ, तब भी क्या आकर्षण बना रहता है।

निष्कर्ष

आधुनिक राज्यों को दोनों प्रकार की शक्ति चाहिए। कठोर शक्ति राज्य को सुरक्षित रखती है, जबकि मृदु शक्ति उसकी सुरक्षा को टिकाऊ और उसके नेतृत्व को स्वीकार्य बनाती है। भारत का एक शक्ति के रूप में उभार

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

दोनों पर टिका है: एक ओर बढ़ती अर्थव्यवस्था और सेना, दूसरी ओर लोकतांत्रिक वैधता और सांस्कृतिक पहुँच।

प्रश्न 3 (अथवा) · इकाई 1 — 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

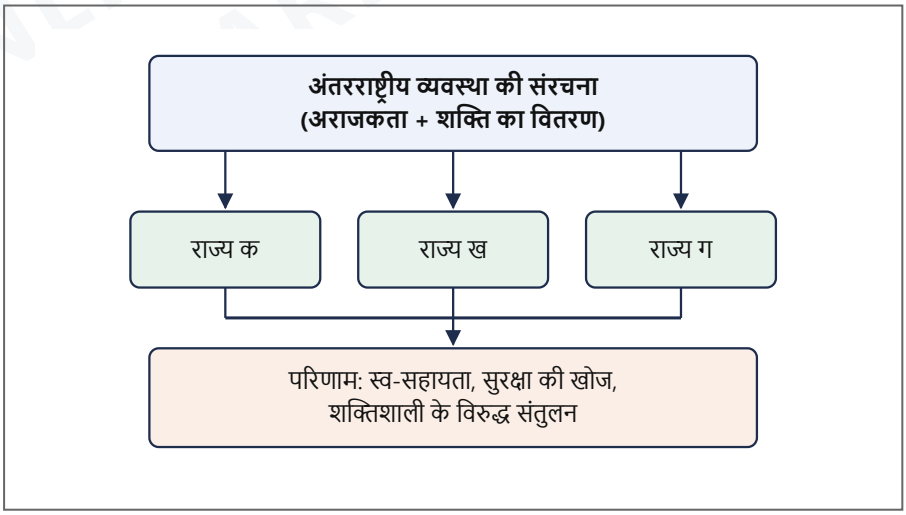
केनेथ वॉल्ट्ज़ के नव-यथार्थवाद (संरचनात्मक यथार्थवाद) को समझाइए। यह परंपरागत यथार्थवाद से कैसे भिन्न है और इसकी सीमाएँ क्या हैं?

भूमिका

नव-यथार्थवाद, जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं, का विकास अमेरिकी विद्वान **केनेथ एन. वॉल्ट्ज़** ने अपनी पुस्तक *थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स* (1979) में किया। वॉल्ट्ज़ ने यथार्थवादियों की यह मान्यता स्वीकार की कि राज्य मुख्य अभिकर्ता हैं और सुरक्षा चाहते हैं, पर व्याख्या बदल दी। उनके अनुसार राज्यों का व्यवहार मुख्यतः मानव स्वभाव से नहीं, बल्कि **अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना** से तय होता है।

वॉल्ट्ज़ के मुख्य विचार

1. **अराजकता:** अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के ऊपर कोई विश्व सरकार नहीं है। हर राज्य को अपने अस्तित्व के लिए स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है (स्व-सहायता)।
2. **संरचना:** व्यवस्था की पहचान तीन बातों से होती है: (क) उसका क्रम-सिद्धांत, यानी अराजकता, (ख) इकाइयों की समानता, क्योंकि सभी राज्य रक्षा और अस्तित्व के समान कार्य करते हैं, और (ग) **क्षमताओं का वितरण**, यानी कितनी महाशक्तियाँ हैं।
3. **सुरक्षा चाहने वाले राज्य:** राज्य जीवित रहना चाहते हैं, इसलिए सुरक्षित स्तर तक शक्ति चाहते हैं, असीमित शक्ति नहीं। इस दृष्टिकोण को *रक्षात्मक यथार्थवाद* कहा जाता है।
4. **परिणाम के रूप में शक्ति-संतुलन:** राज्य इसकी योजना न भी बनाएँ, फिर भी संतुलन अपने आप बनता है क्योंकि कमज़ोर राज्य उभरती शक्ति के विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं।
5. **ध्रुवीयता:** वॉल्ट्ज़ ने कहा कि शीत युद्ध जैसी **द्विध्रुवीय** व्यवस्था बहुध्रुवीय से अधिक स्थिर होती है, क्योंकि दो शक्तियाँ एक-दूसरे को अधिक स्पष्ट रूप से परख पाती हैं और गलत अनुमान की संभावना कम रहती है।



नव-यथार्थवाद: व्यवस्था की संरचना (अराजकता और शक्ति का वितरण) राज्यों के व्यवहार को ढालती है

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

परंपरागत यथार्थवाद से अंतर

आधार	परंपरागत यथार्थवाद (मॉर्गेंथाऊ)	नव-यथार्थवाद (वॉल्ट्ज़)
मुख्य पुस्तक	पॉलिटिक्स अमंग नेशंस (1948)	थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स (1979)
संघर्ष का कारण	मानव स्वभाव और शक्ति की इच्छा	व्यवस्था की अराजक संरचना
शक्ति	स्वयं एक लक्ष्य	अस्तित्व का साधन
विश्लेषण का स्तर	व्यक्ति और राज्य	संपूर्ण व्यवस्था
पद्धति	ऐतिहासिक और दार्शनिक	वैज्ञानिक और सिद्धांत-निर्माण
व्यवहार पर दृष्टि	नेताओं के चुनाव महत्वपूर्ण	संरचना विकल्पों को सीमित करती है

आक्रामक और रक्षात्मक शाखाएँ

जॉन मियरशाइमर ने *द ट्रैजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स* (2001) में **आक्रामक यथार्थवाद** विकसित किया। उनके अनुसार राज्य दूसरों के इरादों के बारे में कभी निश्चित नहीं हो सकते, इसलिए महाशक्तियाँ अधिकतम शक्ति पाने का प्रयास करती हैं और जीवित रहने का सबसे अच्छा तरीका अपने क्षेत्र का प्रभुत्वशाली राज्य बनना है। इसके विपरीत वॉल्ट्ज़ का मत था कि अत्यधिक शक्ति केवल विरोधी संतुलन को भड़काती है।

सीमाएँ और आलोचना

- **परिवर्तन की व्याख्या नहीं:** आलोचकों के अनुसार नव-यथार्थवाद शीत युद्ध के शांतिपूर्ण अंत की भविष्यवाणी या व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि उसने संरचना को स्थिर मान लिया था।
- **घरेलू राजनीति की उपेक्षा:** शासन का स्वरूप, जनमत और नेतृत्व छोड़ दिए जाते हैं।
- **अत्यधिक राज्य-केंद्रित:** अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और गैर-राज्य अभिकर्ताओं को कम स्थान मिलता है।
- **सहयोग की उपेक्षा:** रॉबर्ट कियोहेन जैसे उदार संस्थावादी मानते हैं कि संस्थाएँ अराजकता के प्रभाव घटा सकती हैं।
- **स्थिर और अमूर्त:** अलेक्ज़ेंडर वेंट जैसे रचनावादी कहते हैं कि अराजकता स्थिर नहीं है, 'अराजकता वही है जो राज्य उसे बनाते हैं'।

आज की प्रासंगिकता

नव-यथार्थवादी अमेरिका और चीन की वर्तमान प्रतिद्वंद्विता को शक्ति के वितरण में बदलाव का परिणाम मानते हैं, क्योंकि विश्व एकध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है। वे क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका) जैसे समूह को, जिसे 2021 में नेताओं के स्तर पर पुनर्जीवित किया गया, संतुलन का उदाहरण मानते हैं। आलोचक कहते हैं कि गहरी आर्थिक परस्पर-निर्भरता और घरेलू राजनीति भी इन चुनावों को ढालती है, जिसे केवल संरचनात्मक सिद्धांत नहीं समझा सकता, इसलिए अधिकांश विद्वान अब नव-यथार्थवाद को अन्य उपागमों के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं।

निष्कर्ष

नव-यथार्थवाद ने ध्यान मानव स्वभाव से हटाकर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर लाकर यथार्थवादी परंपरा को अधिक वैज्ञानिक बनाया। यह महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता, गठबंधन-निर्माण और संतुलन समझाने का प्रमुख उपकरण है, पर घरेलू राजनीति, संस्थाओं और विचारों के अध्ययन के बिना अधूरा है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रश्न 4 • इकाई 2 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

परमाणु निवारण (डेटरेंस) के सिद्धांत और परस्पर सुनिश्चित विनाश (MAD) को समझाइए। इसकी शर्तें और आलोचनाएँ क्या हैं?

भूमिका

निवारण (डेटरेंस) का अर्थ है विरोधी को किसी कार्य से रोकना, यह स्पष्ट करके कि उसकी कीमत लाभ से अधिक होगी। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के बाद, और विशेषकर 1949 में सोवियत संघ के अपने बम परीक्षण के बाद, निवारण सामरिक चिंतन का मुख्य विचार बन गया। यह इस विश्वास पर टिका है कि परमाणु हथियार मुख्यतः **युद्ध रोकने** के लिए उपयोगी हैं, लड़ने के लिए नहीं।

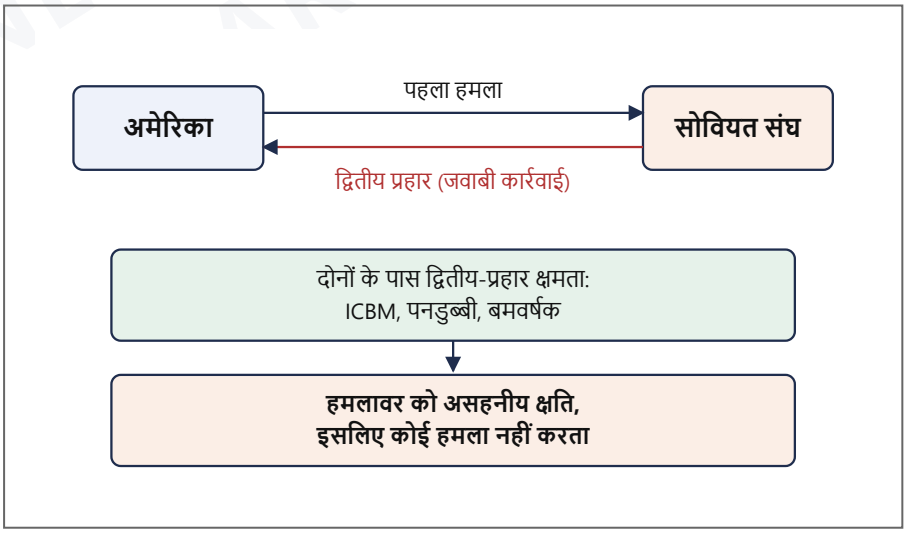
निवारण के प्रकार

1. **दंड द्वारा निवारण:** हमले के बाद भारी जवाबी कार्रवाई की धमकी।
2. **अस्वीकार द्वारा निवारण:** हमले को ही विफल कर देने की क्षमता, जैसे मिसाइल रक्षा।
3. **विस्तारित निवारण:** कोई परमाणु शक्ति अपने सहयोगियों को सुरक्षा का वचन देती है। नाटो सदस्यों पर अमेरिका की 'परमाणु छतरी' इसका मानक उदाहरण है।

परस्पर सुनिश्चित विनाश (MAD)

1960 के दशक तक दोनों महाशक्तियों के पास इतने हथियार हो गए कि **पहले हमले का शिकार होने के बाद भी प्रत्येक दूसरे को नष्ट कर सकती थी**। 1960 के दशक के आरंभ में MAD नाम से जानी गई इस स्थिति का अर्थ था कि पहला हमला आत्मघाती होगा। इसलिए शांति आपसी भय से बनी रही। इसका मुख्य तत्व **द्वितीय-प्रहार क्षमता** है, यानी अचानक हमले में बचे रहकर भी ऐसा जवाब देने की क्षमता जिससे असहनीय क्षति हो। यह **परमाणु त्रय** से सुनिश्चित होती थी:

- मज़बूत भूमिगत साइलो में रखी भूमि-आधारित अंतरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र (ICBM);
- पनडुब्बी से दागी जाने वाली प्रक्षेपास्त्र (SLBM), जिन्हें खोजना कठिन है;
- लंबी दूरी के सामरिक बमवर्षक विमान।



निवारण का तर्क: पहले हमले का जवाब विनाशकारी दूसरे प्रहार से मिलता है, इसलिए कोई हमला नहीं करता

निवारण के काम करने की शर्तें

- **क्षमता:** इतने हथियार जो पहले हमले में बच जाएँ।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **विश्वसनीयता:** विरोधी को विश्वास होना चाहिए कि धमकी सचमुच पूरी की जाएगी।
- **संप्रेषण:** धमकी दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से समझ आनी चाहिए।
- **तर्कसंगतता:** दोनों नेता लागत तौलकर अपने अस्तित्व के हित में कार्य करें।
- **सुरक्षित कमान और नियंत्रण:** ताकि आकस्मिक या अनधिकृत प्रक्षेपण न हो।

शीत युद्ध में भूमिका

माना जाता है कि निवारण ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधे युद्ध को रोका, यहाँ तक कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट जैसे मौकों पर भी। **ए.बी.एम. संधि (1972)** ने मिसाइल रक्षा को कड़ाई से सीमित किया ताकि कोई पक्ष दूसरे की द्वितीय-प्रहार क्षमता कमज़ोर न कर सके और आतंक का संतुलन बना रहे। भारत **विश्वसनीय न्यूनतम निवारण** और **पहले प्रयोग नहीं** की नीति अपनाता है; उसका मसौदा सिद्धांत अगस्त 1999 में जारी हुआ और सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने जनवरी 2003 में उसकी समीक्षा कर उसे अपनाया।

आलोचनाएँ

- **तर्कसंगतता की गारंटी नहीं:** नेता गलत आकलन कर सकते हैं या विचारधारा अथवा घबराहट से प्रेरित हो सकते हैं।
- **दुर्घटना का खतरा:** झूठी चेतावनी से लगभग विनाश हो सकता था। 26 सितंबर 1983 को सोवियत अधिकारी स्टैनिस्लाव पेत्रोव ने आती मिसाइलों की उपग्रह चेतावनी को झूठा संकेत माना और स्थिति को बढ़ने नहीं दिया।
- **शस्त्र-होड़:** सुरक्षित द्वितीय-प्रहार बनाए रखने की ज़रूरत हथियारों के जमाव को बढ़ावा देती है।
- **स्थिरता-अस्थिरता विरोधाभास:** शीर्ष पर परमाणु स्थिरता नीचे छोटे पारंपरिक या परोक्ष संघर्षों को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **नैतिक आपत्ति:** यह नागरिकों के सामूहिक संहार की धमकी पर टिका है, जिसे कई लोग अनैतिक मानते हैं।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं के विरुद्ध कमज़ोर:** आतंकवादियों को उसी प्रकार जवाबी कार्रवाई की धमकी नहीं दी जा सकती।

दक्षिण एशिया में निवारण

भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण-II परीक्षण किए, और पाकिस्तान ने 28 और 30 मई 1998 को चगाई में परीक्षण किए। कुछ विद्वानों का तर्क है कि परमाणु हथियारों ने भारत-पाकिस्तान संघर्षों को सीमित रखने में मदद की, जैसे 1999 के कारगिल संघर्ष में, जबकि अन्य बताते हैं कि 2001-02 का सैन्य गतिरोध और बार-बार के संकट दिखाते हैं कि क्षेत्र खतरे के कितने निकट आया है। यह बहस दिखाती है कि वही सिद्धांत आशावाद का कारण भी माना जा सकता है और चेतावनी भी।

निष्कर्ष

परमाणु निवारण ने परमाणु शक्तियों के बीच तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सहायता की, पर यह तर्कसंगत नेताओं, भरोसेमंद प्रणालियों और भाग्य पर निर्भर है। इसीलिए निःशस्त्रीकरण के समर्थक ऐसी संधियों पर ज़ोर देते रहते हैं जो उन हथियारों को घटाएँ और अंततः समाप्त करें जिन पर निवारण टिका है।

प्रश्न 4 (अथवा) • इकाई 2 — 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

अमेरिका-सोवियत (अमेरिका-रूस) के प्रमुख शस्त्र-नियंत्रण समझौतों, यानी साल्ट, आई.एन.एफ. संधि

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

और स्टार्ट की चर्चा कीजिए। वे कहाँ तक सफल रहे?

भूमिका

शस्त्र-नियंत्रण का अर्थ है हथियारों की संख्या, प्रकार या तैनाती पर सहमत सीमाएँ, जरूरी नहीं कि उन्हें समाप्त किया जाए। यह निःशस्त्रीकरण से भिन्न है, जिसका लक्ष्य हथियार घटाना या समाप्त करना है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दोनों महाशक्तियों ने अपनी प्रतिद्वंद्विता को नियंत्रित करने की ज़रूरत समझी और द्विपक्षीय समझौतों की एक शृंखला चली।

1. साल्ट-I और ए.बी.एम. संधि (1972)

सामरिक शस्त्र सीमा वार्ताएँ 1969 में शुरू हुईं। **26 मई 1972** को मास्को में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेझनेव ने हस्ताक्षर किए:

- **ए.बी.एम. संधि**, जिसने प्रत्येक पक्ष को बहुत छोटी मिसाइल-रक्षा प्रणाली तक सीमित किया, ताकि कोई जवाबी हमले से बचाव की आशा न रख सके;
- एक **अंतरिम समझौता**, जिसने सामरिक प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपकों की संख्या को पाँच वर्ष के लिए स्थिर कर दिया।

साल्ट-I ने हथियार घटाए नहीं, पर समानता और परस्पर असुरक्षा के विचार को स्वीकार किया।

2. साल्ट-II (1979)

18 जून 1979 को वियना में जिमी कार्टर और ब्रेझनेव द्वारा हस्ताक्षरित साल्ट-II ने सामरिक प्रक्षेपकों की कुल संख्या पर बराबर सीमाएँ तय कीं और बहु-शीर्ष (MIRV) पर रोक लगाई। दिसंबर 1979 में सोवियत संघ के अफ़गानिस्तान पर आक्रमण के बाद अमेरिकी सीनेट ने इसकी पुष्टि नहीं की, हालाँकि दोनों पक्षों ने कुछ समय तक इसकी सीमाओं का मोटे तौर पर पालन करने की बात कही।

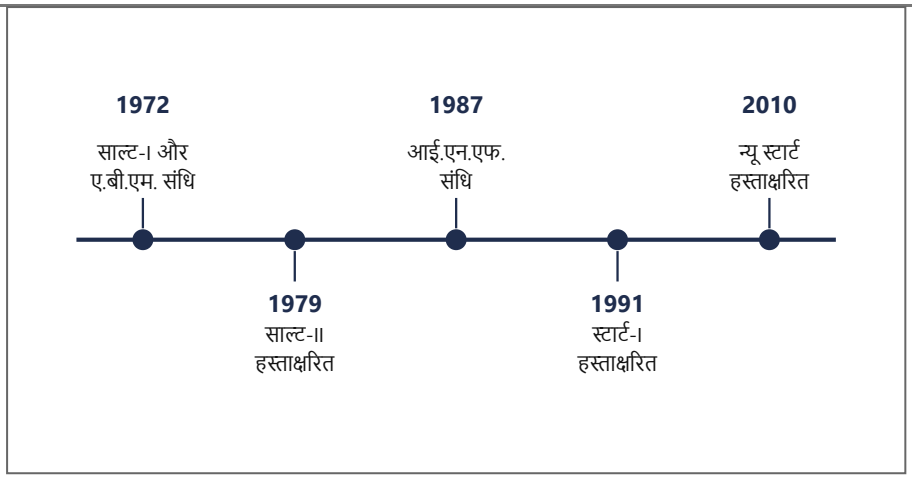
3. आई.एन.एफ. संधि (1987)

8 दिसंबर 1987 को वाशिंगटन में रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव ने इस पर हस्ताक्षर किए और यह 1988 में लागू हुई। इसने **500 से 5,500 किमी मारक दूरी वाली सभी भूमि-प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों** पर प्रतिबंध लगाया। यह पहली संधि थी जिसने परमाणु मिसाइलों की पूरी श्रेणी समाप्त की, और 1991 तक लगभग 2,700 मिसाइलें नष्ट की गईं। इसमें स्थल पर निरीक्षण का भी प्रावधान था, जो सत्यापन में बड़ा कदम था। रूस पर उल्लंघन का आरोप लगाकर अमेरिका अगस्त 2019 में संधि से बाहर हो गया, जिसे रूस ने नकारा।

4. स्टार्ट-I (1991) और न्यू स्टार्ट (2010)

- **स्टार्ट-I** पर 31 जुलाई 1991 को जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश और गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर किए और यह 1994 में लागू हुई। पहली बार इसने सामरिक आयुध **वास्तव में घटाए**, प्रत्येक पक्ष के लिए लगभग 6,000 की सीमा तय की।
- **न्यू स्टार्ट** पर बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने 8 अप्रैल 2010 को प्राग में हस्ताक्षर किए और यह 5 फरवरी 2011 को लागू हुई। इसने प्रत्येक पक्ष को 1,550 तैनात आयुध और 700 तैनात प्रक्षेपकों तक सीमित किया। 2021 में इसे पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।



अमेरिका-सोवियत/रूस शस्त्र-नियंत्रण समझौतों की समय-रेखा, 1972 से 2010

मूल्यांकन

सफलताएँ

- आकस्मिक युद्ध का खतरा घटा और वार्ताओं तथा निरीक्षण से विश्वास बना।
- आई.एन.एफ. और स्टार्ट संधियों ने हथियारों की वास्तविक संख्या घटाई।
- उपग्रह निगरानी और स्थल निरीक्षण जैसी सत्यापन विधियाँ स्वीकृत परंपरा बनीं।

सीमाएँ

- शुरुआती संधियों ने केवल संख्या सीमित की और आधुनिकीकरण तथा नए हथियारों की गुंजाइश छोड़ी, इसलिए शस्त्र-होड़ दूसरे रूपों में चलती रही।
- समझौते राजनीतिक संबंधों पर निर्भर हैं; संधि से बाहर होना और पुष्टि न होना उनकी नाज़ुकता दिखाते हैं।
- केवल दो शक्तियाँ शामिल थीं, जबकि चीन सहित अन्य परमाणु राज्य संधियों से बाहर थे।
- हाइपरसोनिक और अंतरिक्ष हथियार जैसी नई तकनीकें पूरी तरह शामिल नहीं हैं।

सत्यापन क्यों महत्वपूर्ण है

आई.एन.एफ. संधि पर हस्ताक्षर के समय राष्ट्रपति रीगन ने रूसी कहावत 'भरोसा करो, पर जाँच भी करो' का प्रयोग किया। संधि की निरीक्षण व्यवस्था, जिसमें दल एक-दूसरे के मिसाइल अड्डों और कारखानों का दौरा करते थे, ने दिखाया कि समझौतों में वादों के साथ जाँच भी ज़रूरी है। भरोसेमंद सत्यापन के बिना हर पक्ष दूसरे पर धोखे का संदेह करता है, जो संधि को कमज़ोर करता है और उससे बाहर निकलने को बुलावा देता है। इसीलिए विखंडनीय पदार्थ नियंत्रण जैसे आधुनिक निःशस्त्रीकरण प्रस्ताव पारदर्शी और निष्पक्ष निगरानी पर इतना ज़ोर देते हैं।

निष्कर्ष

शस्त्र-नियंत्रण ने परमाणु खतरा समाप्त नहीं किया, पर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा को अधिक अनुमान-योग्य बनाया और आई.एन.एफ. तथा स्टार्ट के मामले में वास्तविक भंडार घटाए। इसका अनुभव बताता है कि स्थायी सीमाओं के लिए राजनीतिक विश्वास और मज़बूत सत्यापन दोनों चाहिए।

प्रश्न 5 • इकाई 3 — 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

1962 के क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन कीजिए: उसकी पृष्ठभूमि, प्रमुख घटनाएँ, समाधान और शीत

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

युद्ध में उसका महत्व।

भूमिका

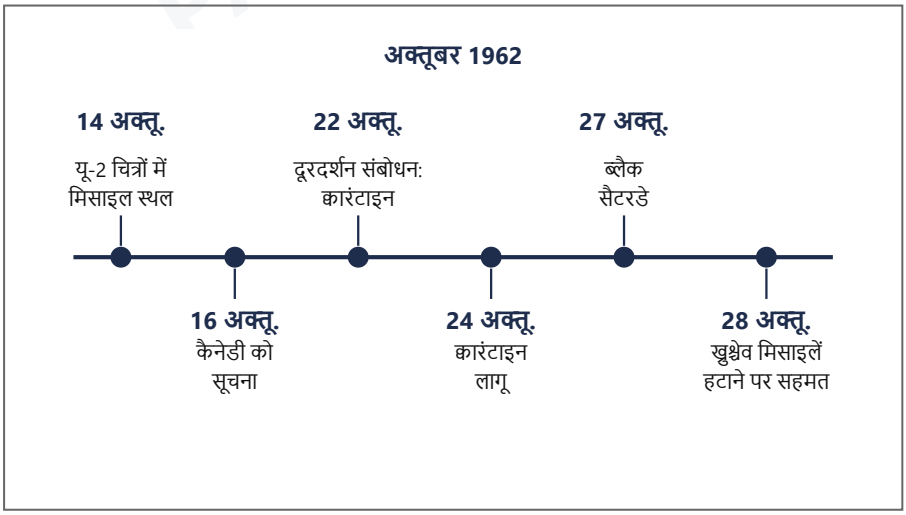
अक्तूबर 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण था, जब अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के सबसे निकट पहुँचे। यह तेरह दिन चला, 16 से 28 अक्तूबर 1962 तक।

पृष्ठभूमि

- **क्यूबा की क्रांति:** फिदेल कास्त्रो 1959 में सत्ता में आए और सोवियत संघ के निकट गए। अमेरिका ने जनवरी 1961 में संबंध तोड़ दिए।
- **बे ऑफ पिग्स (अप्रैल 1961):** क्यूबा के निर्वासितों का अमेरिका-समर्थित आक्रमण विफल रहा, जिससे कास्त्रो को विश्वास हो गया कि एक और हमला होगा।
- **यूरोप में मिसाइल असंतुलन:** अमेरिका ने तुर्की और इटली में जुपिटर मिसाइलें लगाई थीं, जो सोवियत भू-भाग की पहुँच में थीं। सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने संतुलन ठीक करने का अवसर देखा।
- **सोवियत योजना:** 1962 में सोवियत संघ ने गुप्त रूप से क्यूबा में, फ्लोरिडा से केवल लगभग 90 मील दूर, मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलें लगानी शुरू कीं, ताकि क्यूबा की रक्षा हो और उसकी अपनी सामरिक स्थिति सुधरे।

प्रमुख घटनाएँ

तिथि (1962)	घटना
14 अक्तूबर	अमेरिकी यू-2 जासूसी विमान ने निर्माणाधीन मिसाइल स्थलों के चित्र लिए
16 अक्तूबर	राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी को प्रमाण दिखाए गए और उन्होंने एक्सकॉम सलाहकार समूह बनाया
22 अक्तूबर	कैनेडी ने दूरदर्शन पर क्यूबा की नौसैनिक 'क़ारंटाइन' (घेराबंदी) की घोषणा की
24 अक्तूबर	क़ारंटाइन लागू हुई; सोवियत जहाज़ पास आए और फिर लौट गए
26-27 अक्तूबर	ख्रुश्चेव ने दो संदेश भेजे; 27 अक्तूबर, 'ब्लैक सैटरडे', को क्यूबा के ऊपर एक अमेरिकी यू-2 मार गिराया गया
28 अक्तूबर	ख्रुश्चेव ने मिसाइलें हटाने की घोषणा की



क्यूबा मिसाइल संकट की समय-रेखा, 14 से 28 अक्तूबर 1962

'ब्लॉकेड' की जगह 'क़ारंटाइन' शब्द चुना गया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून में ब्लॉकेड युद्ध की कार्रवाई मानी जाती है। कैनेडी ने तत्काल हवाई हमले या आक्रमण को, जिसकी सलाह उनके सैन्य सलाहकारों ने दी थी,

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

अस्वीकार किया और क्रमिक प्रतिक्रिया चुनी जिसमें ख्रुश्चेव को पीछे हटने की जगह मिली।

समाधान

- सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र के सत्यापन में क्यूबा से **मिसाइलें हटाने** पर सहमत हुआ।
- अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से **क्यूबा पर आक्रमण न करने** का वचन दिया।
- एक गुप्त समझ में अमेरिका **तुर्की से अपनी जुपिटर मिसाइलें हटाने** पर भी सहमत हुआ, जो अगले महीनों में किया गया।

परिणाम और महत्व

1. **हॉटलाइन:** 1963 में दोनों शक्तियों ने गलतफहमी से बचने के लिए मास्को-वाशिंगटन सीधी संचार व्यवस्था बनाई।
2. **शस्त्र-नियंत्रण:** आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (अगस्त 1963) ने वायुमंडल, अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षण वर्जित किए।
3. **तनाव-शैथिल्य की शुरुआत:** दोनों नेताओं ने जोखिम की कगार पर चलने के खतरे को समझा और संबंध टकराव से नियंत्रित प्रतिद्वंद्विता की ओर बढ़ने लगे।
4. **राजनीतिक प्रभाव:** ख्रुश्चेव को पीछे हटने वाला माना गया और अक्तूबर 1964 में वे सत्ता से हटा दिए गए; सोवियत संघ ने बाद में अमेरिका के बराबर परमाणु शक्ति पाने का प्रयास किया। कास्त्रो का क्यूबा सोवियत खेमे में दृढ़ता से बना रहा।
5. **संकट-प्रबंधन की सीख:** यह निवारण, सौदेबाज़ी और निर्णय-निर्माण सिद्धांतों का मानक अध्ययन-उदाहरण बन गया।

निर्णय-निर्माण सिद्धांत के लिए सीख

विद्वानों ने इस संकट का गहन अध्ययन किया है। ग्राहम एलिसन की पुस्तक *एसेंस ऑफ़ डिसीज़न* (1971) ने इसके सहारे तीन मॉडलों की तुलना की: **तर्कसंगत अभिकर्ता** मॉडल, जिसमें प्रत्येक सरकार एक एकल गणना करने वाली इकाई की तरह कार्य करती है; **संगठनात्मक प्रक्रिया** मॉडल, जिसमें एजेंसियों की दिनचर्या कार्रवाई को ढालती है; और **नौकरशाही राजनीति** मॉडल, जिसमें अधिकारियों की आपसी सौदेबाज़ी परिणाम तय करती है। इसलिए यह संकट यह समझने में उपयोगी है कि नेता दबाव में निर्णय कैसे लेते हैं और संवाद तथा सोचने का समय क्यों ज़रूरी हैं।

निष्कर्ष

संकट ने दिखाया कि परमाणु हथियारों के कारण महाशक्तियों का सीधा टकराव जोखिम उठाने लायक नहीं रहा। यह सावधान कूटनीति और समझौते से समाप्त हुआ, और इसने दोनों पक्षों को संवाद तथा शस्त्र-नियंत्रण की ओर धकेला, इसलिए इसे शीत युद्ध के इतिहास का मोड़ ठीक ही माना जाता है।

प्रश्न 5 (अथवा) · इकाई 3 — 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की उत्पत्ति, सिद्धांतों और भूमिका को समझाइए। क्या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह प्रासंगिक है?

भूमिका

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) नवस्वतंत्र और विकासशील देशों का समूह था जिन्होंने शीत युद्ध के दौरान **अमेरिकी या सोवियत नेतृत्व वाले किसी सैन्य गुट में शामिल न होने** का निर्णय लिया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

तटस्थता या अलगाव नहीं है। इसका अर्थ है स्वतंत्र विदेश नीति, जिसमें हर मुद्दे को उसके गुण-दोष पर परखने की स्वतंत्रता हो।

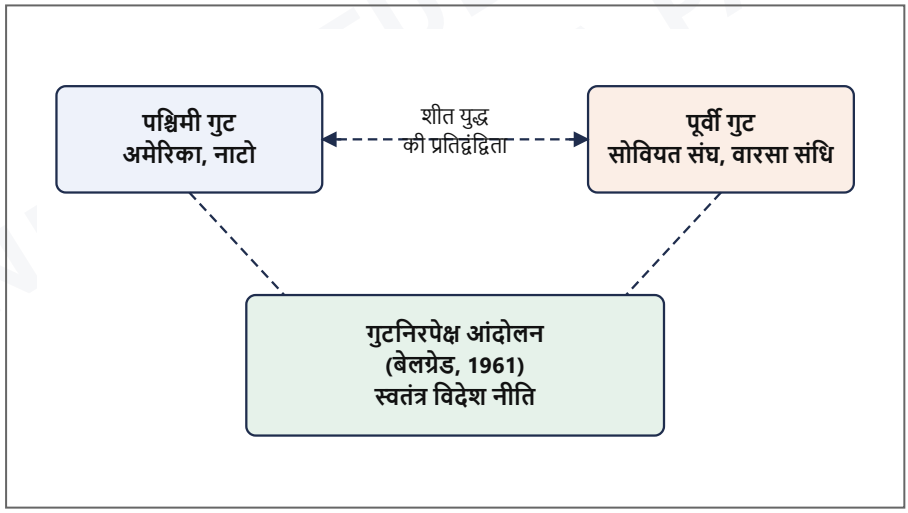
उत्पत्ति

- **पृष्ठभूमि:** 1945 के बाद एशिया और अफ्रीका की कई कॉलोनियाँ स्वतंत्र हुईं। वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना और संसाधन विकास में लगाना चाहती थीं, महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का मोहरा बनना नहीं।
- **बांडुंग सम्मेलन (अप्रैल 1955):** इंडोनेशिया में 29 एशियाई-अफ्रीकी देश मिले और शांति, समानता तथा उपनिवेशवाद-विरोध के सिद्धांत घोषित किए, जिन्होंने NAM की भूमि तैयार की।
- **संस्थापक:** जवाहरलाल नेहरू (भारत), जोसिप ब्रोज़ टीटो (यूगोस्लाविया), गमाल अब्देल नासिर (मिस्र), सुकर्णो (इंडोनेशिया) और क्वामे एनक्रूमा (घाना)।
- **प्रथम शिखर सम्मेलन: बेलग्रेड में 1 से 6 सितंबर 1961** को हुआ, जिसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए।

सिद्धांत

आंदोलन पंचशील (1954) और बांडुंग सिद्धांतों पर आधारित था:

1. सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान;
2. अनाक्रमण और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना;
3. सभी जातियों और राष्ट्रों की समानता;
4. विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व;
5. महाशक्तियों के सैन्य गठबंधनों की सदस्यता नहीं, और उनके हित में अपनी भूमि पर विदेशी अड्डे नहीं;
6. उपनिवेशवाद, नस्लवाद और रंगभेद का विरोध।



शीत युद्ध की दुनिया के तीन खेमे: पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट और गुटनिरपेक्ष देश

भूमिका और उपलब्धियाँ

- **शीत युद्ध का तनाव घटाना:** NAM ने तीसरी आवाज़ दी जो वार्ता, निःशस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण समाधान पर ज़ोर देती थी; उसने शस्त्र-होड़ का विरोध और परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया।
- **उपनिवेशवाद की समाप्ति:** उसने अफ्रीका और एशिया के मुक्ति आंदोलनों का समर्थन किया और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरुद्ध ज़ोरदार अभियान चलाया।
- **आर्थिक माँगें:** उसने 1970 के दशक में जी-77 के साथ **नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था** की माँग की, ताकि विकासशील देशों को अधिक न्यायपूर्ण व्यापार और सहायता मिले।
- **संयुक्त राष्ट्र में आवाज़:** मिलकर कार्य करने से सदस्यों ने विकासशील विश्व को महासभा में बड़ा मत-हिस्सा दिलाया।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- **भारत की भूमिका:** भारत संस्थापक था और बाद में 1983 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई दिल्ली में 7वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की।

कमज़ोरियाँ

सदस्यों के हित अलग थे और कभी-कभी वे किसी गुट की ओर झुके, जैसे 1971 में भारत की सोवियत संघ से संधि की कुछ आलोचना हुई। ईरान और इराक जैसे सदस्यों के विवादों ने एकता कमज़ोर की, और NAM के पास न कोई सेना थी, न प्रवर्तन शक्ति। उसका स्थायी सचिवालय भी नहीं था।

शीत युद्ध के बाद प्रासंगिकता

आलोचक पूछते हैं कि जब दो गुट नहीं रहे तो NAM किसके लिए है। समर्थक कहते हैं कि इसके उद्देश्य अब भी मान्य हैं:

- **अधूरा एजेंडा:** गरीबी, असमान व्यापार, जलवायु न्याय और सुरक्षा परिषद में सुधार।
- **बहुध्रुवीय विश्व:** रणनीतिक स्वायत्तता का विचार फिर लोकप्रिय है, और भारत अपने वर्तमान दृष्टिकोण को 'बहु-संरेखण' या रणनीतिक स्वायत्तता कहता है।
- **सामूहिक आवाज़:** 120 से अधिक सदस्यों वाला NAM संयुक्त राष्ट्र के बाद राज्यों का सबसे बड़ा समूह है।

भारत की व्यावहारिक भूमिका

बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से पहले भी भारत ने अपनी स्वतंत्र स्थिति का उपयोग संघर्षों में सहायता के लिए किया। कोरियाई युद्ध के बाद उसने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की और 1953 में युद्धबंदियों की देखरेख के लिए एक संरक्षक बल भेजा। 1954 में उसने जिनेवा सम्मेलन द्वारा गठित हिंद-चीन के अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोग की अध्यक्षता की। इन कार्यों से भारत को ईमानदार मध्यस्थ के रूप में सम्मान मिला और दिखा कि गुटनिरपेक्षता निष्क्रिय नहीं, रचनात्मक नीति हो सकती है।

निष्कर्ष

NAM ने विभाजित विश्व में नवस्वतंत्र राज्यों को अपनी संप्रभुता बचाने का मार्ग दिया। उसका रूप बदला है, पर स्वतंत्र विदेश नीति और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का उसका मूल विचार विकासशील देशों के लिए आज भी मूल्यवान है।

प्रश्न 6 · इकाई 4 — 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

पंचशील, गुजराल सिद्धांत और 'पड़ोसी पहले' नीति के विशेष संदर्भ में भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।

भूमिका

भारत की विदेश नीति ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आकार लिया, जो 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों थे। इसके मुख्य उद्देश्य हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, आर्थिक विकास को बढ़ावा, और विश्व शांति के लिए कार्य। इसके मूल सिद्धांत काफी स्थिर रहे हैं, यद्यपि समय के साथ उनका रूप बदला है।

मूल सिद्धांत

1. **गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता:** किसी शक्ति-गुट में शामिल हुए बिना हर मुद्दे पर स्वतंत्र निर्णय की स्वतंत्रता।
2. **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा।**

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

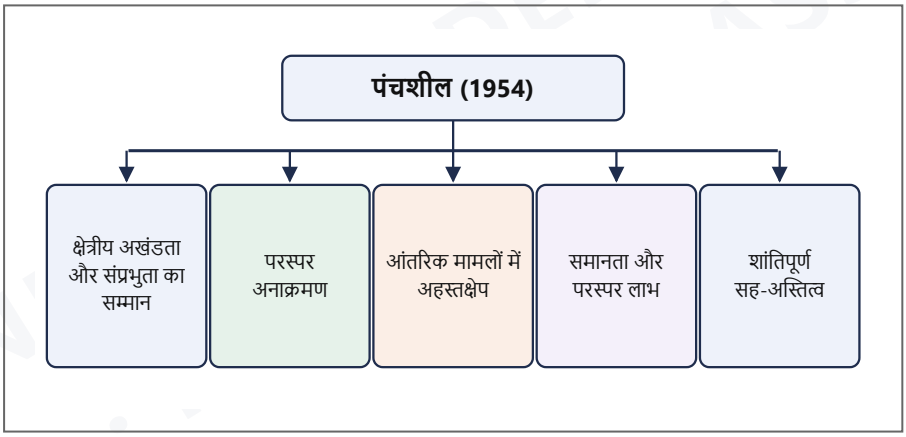
3. **उपनिवेशवाद, नस्लवाद और रंगभेद का विरोध।**
4. **संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय कानून और निःशस्त्रीकरण का समर्थन।**
5. **पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध** और विकास-साझेदारी की भावना।
6. **सांस्कृतिक मूल्य:** *वसुधैव कुटुंबकम्* (विश्व एक परिवार है) का प्राचीन विचार प्रायः भारत के दृष्टिकोण का आधार बताया जाता है।

पंचशील (1954)

पंचशील, यानी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 'पाँच सिद्धांत', पहली बार औपचारिक रूप से **चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार तथा आवागमन समझौते में, 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित**, कहे गए। जून 1954 में नेहरू और चाउ एन-लाई के संयुक्त वक्तव्य में इन्हें दोहराया गया। पाँच सिद्धांत ये हैं:

1. एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान;
2. परस्पर अनाक्रमण;
3. एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर अहस्तक्षेप;
4. समानता और परस्पर लाभ;
5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

ये NAM का नैतिक आधार बने और 1955 की बांडुंग घोषणा में शामिल किए गए। किंतु 1962 के भारत-चीन युद्ध ने केवल सिद्धांतों पर निर्भरता की सीमाएँ दिखाईं, और भारत ने बाद में रक्षा-तैयारी को अधिक महत्व दिया।



पंचशील (1954) के पाँच सिद्धांत

गुजराल सिद्धांत (1996-97)

विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में आई. के. गुजराल ने पड़ोसियों से संबंधों के पाँच सिद्धांत घोषित किए:

1. भारत छोटे पड़ोसियों से **पारस्परिकता** की माँग नहीं करता; वह सद्भाव से जो दे सकता है देता है।
2. कोई दक्षिण एशियाई देश अपनी भूमि का उपयोग दूसरे के हितों के विरुद्ध न होने दे।
3. कोई देश दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।
4. सभी दक्षिण एशियाई देश एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें।
5. सभी विवाद शांतिपूर्ण **द्विपक्षीय वार्ता** से सुलझाए जाएँ।

इसकी उपलब्धियों में बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि (दिसंबर 1996) और नेपाल तथा श्रीलंका से बेहतर संबंध शामिल हैं। आलोचकों को लगा कि बिना पारस्परिकता के देने का शत्रुतापूर्ण राज्य दुरुपयोग कर सकते हैं।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

'पड़ोसी पहले' नीति (2014 के बाद)

2014 के शपथ-ग्रहण, जिसमें सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, के बाद घोषित इस नीति के मुख्य बिंदु हैं:

- सड़क, रेल, विद्युत ग्रिड और डिजिटल संपर्क के माध्यम से **संपर्कता**;
- **व्यापार और जन-जन संपर्क**;
- **त्वरित विकास सहायता** और आपदा में मदद, जैसे 2015 में नेपाल को भूकंप राहत;
- **क्षेत्रीय समूह** जैसे बिम्सटेक और बी.बी.आई.एन. पहल, क्योंकि भारत-पाकिस्तान मतभेदों से सार्क धीमा पड़ा है।

अन्य हालिया दिशाएँ

1991 की पूर्व की ओर देखो नीति 2014 में **एक्ट ईस्ट** बनी। भारत अब रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण की बात करता है, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर एक साथ कई साझेदारों के साथ कार्य किया जाता है।

विदेश नीति के निर्धारक तत्व

इन सिद्धांतों को कई कारक ढालते हैं: **भूगोल** (लंबी भू और समुद्री सीमा तथा हिंद महासागर में स्थिति), **इतिहास** (औपनिवेशिक अनुभव और स्वतंत्रता संग्राम), **आर्थिक आवश्यकताएँ** (ऊर्जा, व्यापार और प्रौद्योगिकी), **सुरक्षा चिंताएँ** (विवादित सीमाएँ और परमाणु पड़ोसी), **घरेलू राजनीति**, और **अंतरराष्ट्रीय परिवेश**। 2015 का सागर (SAGAR) दृष्टिकोण, यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, हिंद महासागर का महत्व दर्शाता है और बताता है कि भूगोल और अर्थव्यवस्था मिलकर नीति को दिशा देते हैं।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद का मेल है। पंचशील ने उसे नैतिक भाषा दी, गुजराल सिद्धांत ने पड़ोसियों के प्रति उदारता, और पड़ोसी पहले ने संपर्कता और गति पर ध्यान, और सभी बदलती दुनिया में राष्ट्रीय हित की सेवा करते हैं।

प्रश्न 6 (अथवा) • इकाई 4 — 10 अंक · ≈ 600–700 शब्द

संयुक्त राष्ट्र के शांति-स्थापना अभियानों और 'संरक्षण की ज़िम्मेदारी' (R2P) के सिद्धांत को समझाइए। उनकी सफलताओं और विफलताओं का मूल्यांकन कीजिए।

भूमिका

संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य, जो उसके चार्टर के अनुच्छेद 1 में है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद की अध्याय VI और VII की औपचारिक शक्तियों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र ने व्यवहार में दो महत्वपूर्ण साधन विकसित किए: 1948 से **शांति-स्थापना (पीसकीपिंग)** और 2005 में अपनाई गई **संरक्षण की ज़िम्मेदारी (R2P)**।

संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना

अर्थ: शांति-स्थापना का अर्थ है संबंधित पक्षों की सहमति से अंतरराष्ट्रीय सैन्य, पुलिस और असैनिक कर्मियों की तैनाती, ताकि युद्धविराम बना रहे और शांति को सहारा मिले। यह शब्द चार्टर में नहीं है; यह शांतिपूर्ण समाधान (अध्याय VI) और प्रवर्तन (अध्याय VII) के बीच आता है, इसलिए इसे कभी-कभी 'अध्याय साढ़े छह' कहा जाता है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

इतिहास: पहले अभियान यू.एन.टी.एस.ओ. (1948, पश्चिम एशिया में) और यू.एन.एम.ओ.जी.आई.पी. (1949, भारत-पाकिस्तान) थे। पहला सशस्त्र बल, **यू.एन.ई.एफ.-I**, स्वेज़ संकट के बाद 1956 में बना, जिसमें कनाडा के लेस्टर पियर्सन का बड़ा योगदान था। संयुक्त राष्ट्र शांति-सैनिकों को **1988 में नोबेल शांति पुरस्कार** मिला।

मूल सिद्धांत:

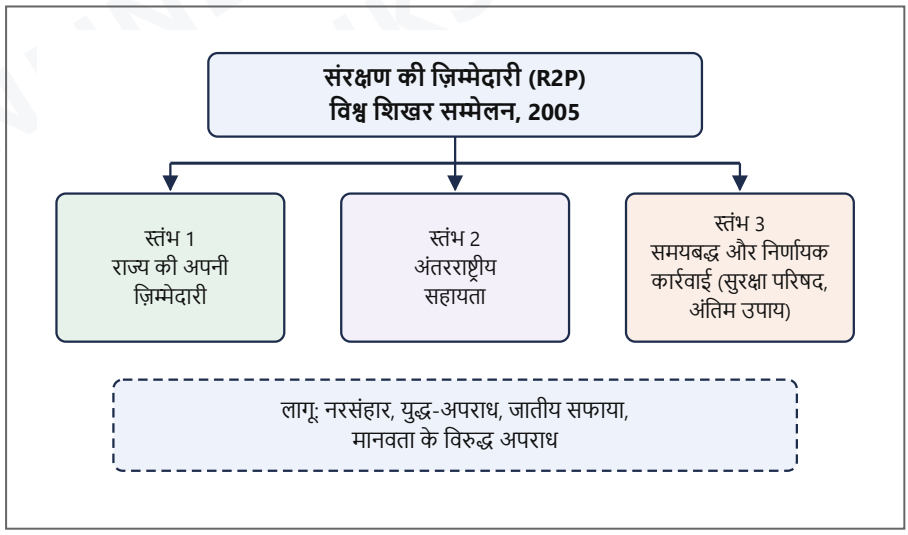
1. मुख्य पक्षों की **सहमति**।
2. सभी पक्षों के प्रति **निष्पक्षता**।
3. आत्म-रक्षा और जनादेश की रक्षा के सिवा **बल का प्रयोग नहीं**।

विकास: शीत युद्ध के बाद कार्य युद्धविराम की निगरानी से बढ़कर 'बहुआयामी' हो गए, जैसे चुनाव कराना, लड़ाकों का निःशस्त्रीकरण, नागरिकों की रक्षा और संस्थाओं का पुनर्निर्माण, जैसा बुतरस बुतरस-घाली की *एन एजेंडा फॉर पीस* (1992) में बताया गया और ब्राहिमी रिपोर्ट (2000) में समीक्षित हुआ। भारत कोरियाई युद्ध के समय से प्रमुख सैनिक-योगदानकर्ताओं में रहा है और भारतीय शांति-सैनिक अफ्रीका तथा अन्य स्थानों के कई अभियानों में रहे हैं।

संरक्षण की ज़िम्मेदारी (R2P)

रवांडा और कोसोवो की विफलताओं के बाद प्रश्न था कि किसी राज्य के भीतर सामूहिक अत्याचारों पर दुनिया कब कार्रवाई कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप और राज्य संप्रभुता आयोग (ICISS) ने 2001 में कहा कि संप्रभुता के साथ **ज़िम्मेदारी** जुड़ी है। **2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के परिणाम-दस्तावेज़** (अनुच्छेद 138-139) ने चार अपराधों के लिए R2P स्वीकार किया: **नरसंहार, युद्ध-अपराध, जातीय सफाया और मानवता के विरुद्ध अपराध**। यह तीन स्तंभों पर टिका है:

1. **राज्य की ज़िम्मेदारी** कि वह अपनी जनता की रक्षा करे।
2. **अंतरराष्ट्रीय सहायता:** दुनिया राज्यों को यह कर्तव्य निभाने में मदद करे।
3. **समयबद्ध और निर्णायक कार्रवाई:** यदि राज्य स्पष्ट रूप से विफल हो, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय सुरक्षा परिषद के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है, अंतिम उपाय के रूप में बल-प्रयोग सहित।



संरक्षण की ज़िम्मेदारी (2005) के तीन स्तंभ

सफलताएँ

- कई अभियानों ने संघर्ष समाप्त कराने तथा चुनावों और पुनर्निर्माण में सहायता की, जैसे नामीबिया (1989-90) और कंबोडिया (1992-93) में।
- शांति-स्थापना वैधता देती है और बड़े युद्धों से सस्ती है।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

- R2P ने लोगों की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय एजेंडा पर रखा और इस पुराने दावे को सीमित किया कि अत्याचार केवल आंतरिक मामला हैं।

विफलताएँ और आलोचनाएँ

- **रवांडा (1994):** संयुक्त राष्ट्र बल छोटा था और जनादेश सीमित था, तथा नरसंहार में लगभग 8 लाख लोग मारे गए।
- **सेब्रेनित्सा (1995):** संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'सुरक्षित क्षेत्र' गिर गया और 8,000 से अधिक बोस्नियाई मुस्लिम पुरुष और लड़के मारे गए।
- **महाशक्तियों पर निर्भरता:** सुरक्षा परिषद में वीटो कार्रवाई रोक सकता है, जैसे सीरिया में।
- **चयनात्मकता और दुरुपयोग:** 2011 में प्रस्ताव 1973 के अंतर्गत लीबिया में नाटो हस्तक्षेप के बाद आलोचकों ने कहा कि R2P का प्रयोग सत्ता-परिवर्तन के लिए हुआ, और भारत तथा ब्राज़ील सहित कई देशों ने अधिक सावधानी की बात की।
- **संसाधनों की समस्या:** सैनिकों, धन और उपकरणों की कमी, और शांति-सैनिकों के दुराचार के मामले।

शांति अभियानों में सुधार

1990 के दशक की विफलताओं के बाद ब्राहिमी रिपोर्ट (2000) ने स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य जनादेश, बेहतर प्रशिक्षित सैनिक और तेज़ तैनाती की माँग की। 2015 में एक उच्च-स्तरीय स्वतंत्र पैनल ने शांति अभियानों की समीक्षा की, और 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रदर्शन और सुरक्षा सुधारने के लिए 'एक्शन फॉर पीसकीपिंग' पहल शुरू की। भारत जैसे सैनिक-योगदानकर्ता देशों ने भी माँग की है कि जनादेश तय करने से पहले उनसे परामर्श हो, क्योंकि जोखिम उनके सैनिक ज़मीन पर उठाते हैं।

निष्कर्ष

शांति-स्थापना और R2P संयुक्त राष्ट्र की अनुकूलन क्षमता दिखाते हैं, पर उनका रिकॉर्ड मिला-जुला है, क्योंकि दोनों सदस्य राज्यों, विशेषकर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर हैं। उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिषद में सुधार और स्पष्ट, यथार्थवादी जनादेश आवश्यक हैं।

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Exam Strategy परीक्षा रणनीति

1. Use dates, treaties and names exactly: 1648 Westphalia, 1946 Iron Curtain speech, 1962 Cuban Missile Crisis, 1972 ABM Treaty, 1998 Rome Statute, 2005 R2P. Examiners reward precise facts.
2. Start every 10-mark answer with a one-line definition or background, then use 4-5 headed sections. A comparison table (for example Realism vs Neo-realism) earns easy marks.
3. Link theory with practice: after each concept give one real example (Cuban Missile Crisis for deterrence, Rwanda and Libya for R2P, India's 2003 doctrine for nuclear policy).
4. Draw a small labelled diagram or timeline wherever the question allows; a neat timeline of the Cuban Missile Crisis is worth more than a paragraph.
5. Write the India angle in every Unit 2 and Unit 4 answer: no first use, refusal to sign the NPT and CTBT, peacekeeping contributions and the demand for UNSC reform.
6. Keep the tone analytical and neutral, especially on the Palestine-Israel conflict. State facts, positions and international resolutions, not personal opinions.
7. Attempt all five short questions and give each 4-mark answer about 100-120 words in 4-5 crisp points.

1. तिथियाँ, संधियाँ और नाम सही-सही लिखें: 1648 वेस्टफेलिया, 1946 आयरन कर्टेन भाषण, 1962 क्यूबा मिसाइल संकट, 1972 ए.बी.एम. संधि, 1998 रोम संविधि, 2005 आर2पी। परीक्षक सटीक तथ्यों पर अंक देते हैं।
2. हर 10 अंक के उत्तर की शुरुआत एक पंक्ति की परिभाषा या पृष्ठभूमि से करें, फिर शीर्षकों वाले 4-5 भाग लिखें। तुलना की तालिका (जैसे यथार्थवाद बनाम नव-यथार्थवाद) से आसान अंक मिलते हैं।
3. सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ें: हर अवधारणा के बाद एक वास्तविक उदाहरण दें (निवारण के लिए क्यूबा संकट, आर2पी के लिए रवांडा और लीबिया, परमाणु नीति के लिए भारत का 2003 का सिद्धांत)।
4. जहाँ प्रश्न अनुमति दे वहाँ छोटा नामांकित चित्र या समय-रेखा बनाएँ; क्यूबा मिसाइल संकट की साफ़ समय-रेखा एक अनुच्छेद से अधिक अंक दिलाती है।
5. इकाई 2 और इकाई 4 के हर उत्तर में भारत का पक्ष लिखें: पहले प्रयोग नहीं की नीति, एन.पी.टी. और सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर से इनकार, शांति-स्थापना में योगदान और सुरक्षा परिषद में सुधार की माँग।
6. भाषा विश्लेषणात्मक और तटस्थ रखें, विशेषकर फ़लस्तीन-इज़राइल संघर्ष पर। तथ्य, पक्ष और अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव लिखें, निजी राय नहीं।
7. पाँचों लघु प्रश्न हल करें और हर 4 अंक का उत्तर 4-5 स्पष्ट बिंदुओं में लगभग 100-120 शब्दों में लिखें।

Final reminder / अंतिम सलाह: This Demo Set shows how our answers are written. For the full sets, open the Pariksha Pass App. Whatever you practise, revise the entire syllabus. यह डेमो सेट हमारे उत्तरों की शैली दिखाता है। पूरे सेट के लिए परीक्षा पास ऐप खोलें। जो भी अभ्यास करें, पूरा पाठ्यक्रम दोहराएँ।

Online Student Seva · Pariksha Pass App · Edition Oct 2026

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

Unlock the full sets in the Pariksha Pass App पूरे सेट परीक्षा पास ऐप में अनलॉक करें

You have just seen one Demo Set. The full Guessing Papers for your university, course and subject are available inside the **Pariksha Pass App**, brought to you by **Online Student Seva**.

आपने अभी एक डेमो सेट देखा है। आपके विश्वविद्यालय, कोर्स और विषय के पूरे गेसिंग पेपर **ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा** की **परीक्षा पास ऐप** में उपलब्ध हैं।

What a full paper set contains

- Up to three sets for each subject: Set A (Most Probable), Set B (Highly Likely) and Set C (Alternate).
- In every set: 10 objective questions with explanations, 5 short-answer questions and 8 long-answer questions (4 units, each with an internal choice), all with model answers.
- Every answer in English and in full, independent Hindi, with labelled diagrams, tables and worked solutions where the subject needs them.
- A syllabus-coverage page, a list of the prescribed books and a subject-specific exam-strategy page.

पूरे सेट में क्या मिलता है

- हर विषय के अधिकतम तीन सेट: सेट A (सबसे संभावित), सेट B (अधिक संभावित) और सेट C (वैकल्पिक)।
- हर सेट में: स्पष्टीकरण सहित 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 इकाइयाँ, प्रत्येक में आंतरिक विकल्प), सभी के आदर्श उत्तर सहित।
- हर उत्तर अंग्रेज़ी में और पूर्ण, स्वतंत्र हिन्दी में, जहाँ विषय को आवश्यकता हो वहाँ नामांकित चित्र, तालिकाएँ और हल किए गए उदाहरण सहित।
- पाठ्यक्रम-कवरेज पृष्ठ, अनुशंसित पुस्तकों की सूची और विषय-विशेष परीक्षा-रणनीति पृष्ठ।

Please note / कृपया ध्यान दें: Questions in the full sets are chosen from the syllabus on the basis of high-probability topic coverage. No set can promise which questions will appear in the examination, so always prepare the complete syllabus from your text book.

पूरे सेटों के प्रश्न पाठ्यक्रम से अधिक संभावित टॉपिक कवरेज के आधार पर चुने जाते हैं। कोई भी सेट यह वादा नहीं कर सकता कि परीक्षा में कौन-से प्रश्न आएँगे, इसलिए अपनी पाठ्यपुस्तक से पूरा पाठ्यक्रम अवश्य तैयार करें।

Online Student Seva · Pariksha Pass App
ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · परीक्षा पास ऐप

Download Pariksha Pass App >

Get all 3 full Guessing Paper sets on Google Play

© Online Student Seva · Exclusive property · Accessible only through the Pariksha Pass App · Copying, sharing or selling is strictly prohibited and will invite serious legal action.
© ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा · विशेष संपत्ति · केवल परीक्षा पास ऐप पर उपलब्ध · कॉपी, शेयर या बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।